श्याम सुंदर और ए. एन. आर.

वी.

राम कुमार और ए. एन. आर

31 जुलाई, 2001

[एस. पी. भरुचा, वी. एन. खरे, एन. संतोश हेगड़े, वाई. के. सभरवाल और शिवराज वी. पाटिल, जे. जे.)

पंजाब पूर्व-प्रवर्तन अधिनियम-धारा 15-हरियाणा संशोधन अधिनियम, 1995 -

मुक़दमे की भूमि की बिक्री-मुक़दमे के सह-भागीदारों का बिक्री से पहले खाली करने का अधिकार-निचली अदालत ने सह-भागीदारों के पक्ष में फैसला सुनाया-एक के माध्यम से वापस लिया गया अधिकार

अपील के लंबित रहने के दौरान अधिनियम में संशोधन-विचार का प्रभाव

अपीलीय न्यायालय द्वारा संशोधन का-अभिनिर्धारित, वाद की डिक्री के बाद पूर्व-प्रवर्तन का अधिकार पूर्व-रिक्तकर्ता का एक निहित अधिकार है-अपीलीय न्यायालय अपील के लंबित रहने के दौरान अधिनियम में बाद के संशोधन पर विचार नहीं कर सकता है और निचली अदालत द्वारा डिक्री पारित करने पर अर्जित निहित अधिकार को छीन नहीं सकता है -

संशोधित धारा स्पष्ट रूप से या निहित रूप से पूर्वव्यापी नहीं है संशोधन अधिनियम एक घोषणात्मक अधिनियम नहीं है-इसलिए, इसमें कोई पूर्वव्यापी नहीं है। ऑपरेशन।

क़ानूनों की व्याख्या:

लाभकारी विधान-हितकारी निर्माण का नियम-लागू होना-- माना जाता है कि संशोधन अधिनियम एक लाभकारी विधान है हितकारी निर्माण का नियम अधिनियम की संशोधित धारा का अर्थ लगाते हुए लागू नहीं होता है-यह नहीं माना जा सकता है कि एक हितकारी विधान हमेशा पूर्वव्यापी होता है।

भले ही यह कानून में स्पष्ट रूप से या निहित रूप से नहीं कहा गया हो।

अपीलकर्ताओं ने विक्रेताओं से बिक्री विलेख के माध्यम से सूट भूमि खरीदी। प्रत्यर्थियों ने निचली अदालत के समक्ष एक मुकदमा दायर किया जिसमें इस आधार पर बिक्री को पहले से खाली करने के तरजीही अधिकार का दावा किया गया कि वे मुकदमे की भूमि के सह-हिस्सेदार थे। द.

विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों के पक्ष में वाद का फैसला सुनाया गया। उत्तरदाताओं ने आदेश 20 नियम 14 के तहत आवश्यक खरीद राशि जमा की सीपीसी। अपीलकर्ता अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के समक्ष सफल नहीं हुए। इसलिए उन्होंने इस अदालत का रुख किया। अपील के लंबित रहने के दौरान। पंजाब पूर्व-प्रवर्तन अधिनियम (अधिनियम) की धारा 15 (1)

(बी) को हरियाणा संशोधन अधिनियम, 1995 (संशोधन अधिनियम) के माध्यम से एक नई धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

जिसके तहत सह-भागीदार का बिक्री से पहले खाली करने का अधिकार वापस ले लिया गया था। जब इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए अपीलें आईं, तो पीठ ने दीदार सिंह आदि में इस न्यायालय के दो परस्पर विरोधी निर्णयों पर विचार किया। वी. इशर सिंह (मृत)

एलआरएस द्वारा। आदि। , (1995) 1 स्केल 1 और रामजीलाल और अन्य। , आदि वी। घिसा राम आदि।

जे. टी. (1996) 2 एस. सी. 649 ने 1995 में किए गए संशोधन के प्रभाव के सवाल पर अपीलों को संविधान पीठ को भेज दिया।

अपीलार्थियों ने तर्क दिया कि सह-भागीदार के रूप में उत्तरदाताओं का अधिकार

अधिनियम की प्रतिस्थापित धारा 15 को देखते हुए पूर्व-खाली बिक्री को समाप्त कर दिया गया था; कि अपील मुकदमे की निरंतरता होने के कारण, यह न्यायालय सक्षम है

अधिनियम में किए गए विधायी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए; कि

अपीलीय न्यायालय केवल यह देखने के लिए प्रतिबंधित नहीं है कि क्या निचली अदालत का निर्णय पक्षकारों के अधिकारों के आधार पर सही था। वाद का न्यायनिर्णयन करना लेकिन बाद के परिवर्तनों पर विचार करना और उन्हें प्रभावी बनाना

कानून में जिसके तहत अपील के लंबित रहने के दौरान सह-भागीदार का पूर्व-समावेशन का अधिकार छीन लिया गया है; कि एक संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किए गए अधिनियम में एक प्रतिस्थापित धारा को पूर्वव्यापी संचालन माना जाना चाहिए; कि संशोधन अधिनियम प्रकृति में घोषणात्मक होने के कारण, पूर्वव्यापी प्रभाव रखता है और परिणामस्वरूप वाद की डिक्री की तारीख पर प्रतिवादी का जो भी अधिकार था वह समाप्त हो गया; और यह कि संशोधन अधिनियम, जो नागरिकों के सामान्य हित के लिए पारित एक लाभकारी कानून है, परोपकारी निर्माण के नियम को लागू करके पूर्वव्यापी संचालन करेगा।

प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि पूर्व-प्रवर्तन के लिए एक मुकदमे में, एक दावेदार

विचारण न्यायालय की डिक्री की तारीख को अपना अधिकार साबित करना है और हारना है

वाद की स्थिरता पर; कि यह मानते हुए कि अपील वाद की निरंतरता है, संशोधन अधिनियम का कोई पूर्वव्यापी संचालन नहीं है जो विचारण न्यायालय की डिक्री को प्रभावित करेगा; कि आदेश 20 नियम 14 सी. पी. सी. के प्रावधानों को देखते हुए, संपत्ति का अधिकार पहले से ही खरीद धन जमा करने पर पारित किया जा चुका था और इसलिए, संशोधन अधिनियम स्वामित्व को प्रभावित नहीं करता है। उन्हें प्राप्त किया।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने पकड़ना: 1.1 . पूर्व-समावेशन के अधिकार की उत्पत्ति प्रथा के आधार पर होती है।

जिसे बाद में तत्कालीन ग्रामीण समुदाय और समाज की अखंडता के संरक्षण और शांति और सुरक्षा के रखरखाव की आवश्यकता के कारण संहिताबद्ध किया गया था। परिवर्तित परिस्थितियों में, पूर्व-प्रवर्तन के अधिकार को पुराना कहा जा सकता है, 117

श्याम सुंदर बनाम। राम कुमार

लेकिन जब तक इसे वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है, तब तक इसे समान व्यवहार दिया जाना चाहिए। जैसा कि कोई अन्य कानून योग्य है। सह-हिस्सेदार के पूर्व-अधिग्रहण का अधिकार भूमि से जुड़ी संपत्ति की एक घटना है। यह एक तरह का बोझ है।

भूमि के साथ ले जाना, जिसे भूमि के सह-मालिक द्वारा या उसके खिलाफ लागू किया जा सकता है। पूर्व-उत्सर्जन के अधिकार के पीछे मुख्य उद्देश्य या तो आधारित है प्रथा या वैधानिक कानून परिवार की संपत्ति या संपत्ति में अजनबी की घुसपैठ को रोकने के लिए है। एक सह-हिस्सेदार को, पूर्व-प्रवर्तन के कानून के तहत, एक अधिकार है

उसके द्वारा खरीदी गई संपत्ति के हिस्से के संबंध में किसी अजनबी के स्थान पर खुद को प्रतिस्थापित करना, जिसका अर्थ है कि जहां कोई सह-भागीदार अपने हिस्से को हस्तांतरित करता है। धारित करते हुए, दूसरे सह-भागीदार को इस तरह के हस्तांतरण पर वीटो करने का अधिकार है और इस तरह अजनबी को उस क्षेत्र में होल्डिंग प्राप्त करने से रोकता है जहां

प्री-एम्प्शन प्रबल है। वर्तमान में इस तरह के अधिकार को पुरातन माना जा सकता है। सामंती और आधुनिक लेकिन यह लगभग दो शताब्दियों तक या तो प्रथा या वैधानिक कानून पर आधारित कानून था। यह इस पृष्ठभूमि में है कि अधिकार

वैधानिक कानून के तहत पूर्व-समावेशन को अनिवार्य माना गया है न कि केवल विवेकाधीन। न्यायालय के पास किसी अन्य सह-हिस्सेदार द्वारा किसी संपत्ति की बिक्री के लिए पूर्व-अधिनिर्णय की डिक्री देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस कारण से, न्यायालयों ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया कि जहां किसी सह-हिस्सेदार द्वारा स्वामित्व या संपत्ति की बिक्री होती है, वहां सम्राट द्वारा बिक्री की तारीख को, वाद दायर करने की तारीख को, और पहली बार के न्यायालय की डिक्री की तारीख को या विक्रेता द्वारा अपनी स्थिति में सुधार करने की तारीख को, जब तक कि पूर्व-समावेशन के लिए मुकदमे का निर्णय नहीं हो जाता है और मुकदमे के निर्णय के बाद, पूर्व-निवेदक या विक्रेता द्वारा अपनी स्थिति में सुधार करने की योग्यता का कोई नुकसान नहीं होता है। [130 - ए-एफ।

1.2 . कुछ संदर्भ में, यह सच है कि एक अपील एक की निरंतरता है

वाद और अपीलीय न्यायालय वाद की पुनः सुनवाई कर रहा है, लेकिन इस तरह की व्यापक अपीलीय शक्ति का उपयोग किसी पूर्व-रिक्तकर्ता के निहित अधिकार को प्रभावित करने के लिए नहीं किया जाता है। यह है।

यह विवादित नहीं है कि दावेदार का विक्रेता की वरीयता में संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार मुकदमे के निर्णय की तारीख तक एक अनुचित अधिकार है, लेकिन यह दावेदार के पक्ष में डिक्री पारित होते ही प्रभावी हो जाता है। आदेश 20 नियम 14 (1) सी. पी. सी. के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, दावेदार द्वारा न्यायालय में खरीद राशि जमा करने पर संपत्ति का अधिकार और अधिकार पूर्व-खाली करने

वाले का निहित अधिकार बन जाता है। डिक्री से पहले पूर्व अभिग्रहण का अधिकार कमजोर हो सकता है लेकिन यह निहित अधिकार बनने के बाद, इसे केवल कानून की ज्ञात विधि से ही छीन लिया जा सकता है। अपील की विचाराधीनता के दौरान पूर्व-रिक्तकर्ता या विक्रेता की योग्यता के नुकसान को न्यायालय को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि एक अपीलीय न्यायालय मुख्य रूप से 118 द्वारा दिए गए निर्णय की शुद्धता से संबंधित है।

अपील के लंबित रहने के दौरान होने वाली बाद की घटना पर विचार करना। और एक उपयुक्त मामले में एक न्यायालय शिकायत या लिखित संशोधन की अनुमति देता है।

कार्यवाही की बहुलता से बचें न कि जहां इस तरह के संशोधन का कारण बनता है वादी के निहित अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह उसे बिना उपचार के प्रस्तुत करता है। यह है।

इस प्रकार केवल वे घटनाएँ जो पहले हुई हैं या पक्षों के अधिकार

पूर्व-अभियोग वाद के निर्णय के लिए और जिसका विचारण न्यायालय हकदार था

निपटान, केवल अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार में लिया जा सकता है।

[131 - ई-एच; 132-ए-सी]

1.3 . एक पूर्व-प्रवर्तन मामले में, जहां डिक्री के खिलाफ अपील दायर की जाती है

पहली बार के न्यायालय में, अपील का दायरा प्रश्न तक ही सीमित है। विचारण न्यायालय का निर्णय सही है या नहीं। यह कानूनी है

स्थिति, जिसने एक सदी से अधिक समय तक मैदान पर कब्जा किया, उसके बाद की कोई भी घटना अपील के लंबित रहने के दौरान जगह को लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है

अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार। अन्यथा यह एक के मामले को विस्थापित कर सकता है

प्री-एम्प्टर। [132 - डी-ई]

दीदार सिंह आदि। वी. एलआरएस द्वारा इशर सिंह (मृत)। आदि। , [1995 | 1 पैमाना

1 ; भगवान दास (डी) एलआरएस द्वारा। और ओआरएस। वी. चेत राम, [1972] 2 एससीआर 640 और रिखी

राम और अन्र। वी. राम कुमार और अन्य। , [1975] 2 एस. सी. सी. 318, पर भरोसा किया।

सकीना बीबी बनाम। अमीरान और ओआरएस। , (1888) आई. एल. आर. 10 इलाहाबाद 472; बलदेव

मिसिर वी। राम लगान शुकुल, (1923) आई. एल. आर. 45 इलाहाबाद 709; हंस नाथ और अन्य। वी. राघौ प्रसाद सिंह, 59 द लॉ रिपोर्ट्स इंडियन अपील्स 138; माधो सिंह बनाम। लेफ्टिनेंट जेम्स

आर. आर. एस. किनर, (1942) आई. एल. आर. 23 लाहौर 155 (एफ. बी.); ज़हूर दीन और अन्र। वी. जलाल दीन नूर मोहम्मद और अन्य। , (1994) आई. एल. आर. 25 लाहौर 443 (एफ. बी.) और रामजी लाल और अन्र। वी. पंजाब राज्य और अन्य। , (1996) एलएलआर 19 (2) पंजाब 125 (एफबी) को मंजूरी दी गई।

रामजीलाल और ओआरएस। आदि वी। घिसा राम आदि, जे. टी. (1966) 2 एस. सी. 649 और करण

सिंह और ओआरएस। वी. भगवान सिंह (मृत) एल. आर. एस. और ओआरएस। , [1996] 7 एस. सी. सी. 559, खारिज कर दिया गया।

2.1 . जब किसी अधिनियम को निरस्त करने के बाद एक नया कानून बनाया जाता है,

ऐसा विधान वाद या वाद के निर्णय की तिथि पर पक्षों के मूल अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है जब तक कि यह एक पूर्वव्यापी विधान न हो और एक अपीलीय न्यायालय अपील किए गए निर्णय के बाद अस्तित्व में लाए गए एक नए कानून पर विचार नहीं कर सकता है क्योंकि अपील में पक्षों के अधिकार उस पर लागू कानून के तहत निर्धारित किए जाते हैं।

सूट की तारीख। हालांकि, श्याम सूर्य बनाम में कानून की स्थिति अलग होगी।

राम कुमार

119

दलों को चिंता है कि वे संशोधन से अप्रभावित रहते हैं अधिनियमन। इसलिए, जहां किसी अधिनियम के प्रावधानों के निरसन का पालन किया जाता है

एक संशोधन अधिनियम द्वारा नए कानून द्वारा, ऐसा कानून संभावित है

संचालन और पार्टियों के मूल या निहित अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है जब तक कि

पूर्वव्यापी या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से किया गया। वहाँ एक है

एक क़ानून के पूर्वव्यापी संचालन के खिलाफ धारणा और आगे एक कानून को इससे बड़ा पूर्वव्यापी संचालन नहीं माना जाना चाहिए

इसकी भाषा आवश्यक बनाती है, लेकिन एक संशोधन अधिनियम जो प्रभावित करता है

प्रक्रिया को पूर्वव्यापी माना जाता है, जब तक कि संशोधन अधिनियम में प्रावधान न हो। अन्यथा। [136 बी-सी]

राम सरूप बनाम। मुंशी और ओआरएस। , [1963] 3 एस. सी. आर. 858 (सी. बी.); अमीर सिंह और

एन. आर. वी. राम सिंह और ओआरएस। , [1963] 3 एस. सी. आर. 884 (सी. बी.); गरिकापति वीराया बनाम। एन. सुब्बैया चौधरी, [1957] एससीआर 488; श्रीमती. दयावैत और अन्र। वी. इंद्रजीत और

ओआरएस। , [1966] 3 एस. सी. आर. 275; हितेंद्र विष्णु ठाकुर और अन्य। वी. महाराष्ट्र राज्य और ओआरएस। , [1994] 4 एससीसी 602; के. एस. परिपूर्णन बनाम केरल राज्य और अन्य। , [1994]

5 एस. सी. सी. 593; लच्मेश्वर प्रसाद शुकुल और अन्य। वी. केशवरलाल चौधरी

और ओआरएस। , आकाशवाणी (1941) संघीय न्यायालय 5; शांतिदेवी (श्रीमती) एन. आर. वी. हुकुम चंद,

[1996] 5 एस. सी. सी. 768; राम लाल बनाम। राजा राम और अन्र। , (1960) पंजाब लॉ रिपोर्टर

291 ; अमरजीत कौर आदि। प्रीतम सिंह और ओआरएस। आदि, [1974] 2 एस. सी. सी. 363 और

साधु सिंह और अन्र। वी. धरम देव और ओआरएस। , आकाशवाणी (1980) एस. सी. 1654, निर्दिष्ट

को।

क़ानूनों की व्याख्या पर मैक्सवेल, 12 वीं संस्करण। ; फ्रांसिस बेनिओन

सांविधिक व्याख्या, द्वितीय संस्करण। , संदर्भित किया गया।

2.2 . पंजाब पूर्व-उद्ग्रहण अधिनियम की नई प्रतिस्थापित धारा 15

हरियाणा संशोधन अधिनियम 1995 या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से पूर्वव्यापी नहीं है जो मुकदमे के निर्णय की तारीख पर पक्षों के अधिकार को प्रभावित कर सकता है और इसे लागू करने की आवश्यकता है।

अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार। अधिनियम की प्रतिस्थापित धारा 15, जिसमें यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि यह पूर्वव्यापी है, उन पक्षों के अधिकार को प्रभावित नहीं करती है जो उन्हें मुकदमे की तारीख या पहली बार अदालत द्वारा डिक्री पारित करने की तारीख को अर्जित हुए थे। वर्तमान अपील कानून में परिवर्तन से अप्रभावित हैं जहां तक यह पक्षों के मूल अधिकारों के निर्धारण से संबंधित है और उन पर निर्णय पूर्व-प्रवर्तन कानून के आलोक में लिया जाना आवश्यक है जैसा कि डिक्री पारित होने की तारीख को मौजूद था। एक अधिनियम में एक प्रतिस्थापित धारा एक संशोधन अधिनियम का उत्पाद है और सभी एक ही संशोधन अधिनियम के मामले में आने वाले प्रभाव और परिणाम 120

एस सी आर।

एक अधिनियम में प्रतिस्थापित धारा के मामले में भी इसका पालन किया जाएगा।

[136 - ई-एफ-जी-एच; 137-ए]

शांतिदेवी (श्रीमती) और अन्र। वी. हुकुम चंद, [1996] 5 एस. सी. सी. 768, पर भरोसा किया।

3.1 . आम तौर पर व्याख्या के नियम न्याय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में न्यायालय की सहायता के लिए होते हैं। इसलिए, यह परोपकारी निर्माण के नियम के अनुप्रयोग के मामले में भी सच है। यदि नियम के लागू होने पर परोपकारी निर्माण, न्यायालय ने पाया कि यह अपने भीतर न्याय कर रहा होगा

कानून के मापदंडों, तो वर्तमान मामले में निर्माण के ऐसे नियम के लागू होने का कोई कारण नहीं है। लेकिन न्यायालय की शक्तियों पर सीमाएं हैं, इस अर्थ में कि न्यायालय, कुछ स्थितियों में, अक्सर परोपकारी या उदार निर्माण के नियम को लागू करने से खुद को रोकते हैं। न्यायिक उदाहरणों ने उन स्थितियों को निर्धारित किया है जहां और जब परोपकारी शासन होता है

. निर्माण को लागू करने की आवश्यकता है। स्थितियों में से एक यह है कि जब न्यायालय यह पाता है कि परोपकारी निर्माण के नियम को लागू करके वह क़ानून के प्रावधान को या तो प्रतिस्थापित करके, जोड़कर या बदलकर फिर से कानून बनाएगा।

अधिनियम के प्रावधान में उपयोग किए गए शब्द। ऐसी स्थिति में आम तौर पर न्यायालयों ने परोपकारी निर्माण के नियम को लागू करने से खुद को दूर रखा है। परोपकारी निर्माण के नियम को लागू करने की आड़ में, एक न्यायालय को मूर्ति के प्रावधान को फिर से कानून बनाने और अधिनियम के प्रावधान की भावना के साथ हिंसा करने का अधिकार नहीं है। दूसरी स्थिति तब होती है जब किसी क़ानून में उपयोग किए गए शब्द केवल एक अर्थ के लिए सक्षम होते हैं। ऐसी स्थिति में, अदालतें परोपकारी निर्माण के नियम को लागू करने में संकोच करती रही हैं। लेकिन यदि यह पाया जाता है कि क़ानून में उपयोग किए गए शब्द एक से अधिक अर्थों को जन्म देते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय निर्माण के ऐसे नियम को लागू करने से वंचित नहीं हैं। तीसरी स्थिति तब होती है जब इस तरह से माने गए क़ानून के प्रावधान में कोई अस्पष्टता नहीं होती है। यदि किसी कानून का प्रावधान स्पष्ट, असंदिग्ध है और किसी भी संदेह को जन्म नहीं देता है, तो ऐसी परिस्थितियों में

परोपकारी निर्माण के नियम का कोई अनुप्रयोग नहीं है। हालाँकि, यदि यह पाया जाता है कि किसी अधिनियम के प्रावधानों में उपयोग किए गए प्रावधान या शब्द के अर्थ के संबंध में कोई संदेह है, तो अदालत को परोपकारी नियम लागू करने की अनुमति है।

अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए निर्माण। आम तौर पर, का नियम

कल्याणकारी कानूनों या कमजोर और मजबूत अनुबंध करने वाले पक्षों के बीच संबंधों से संबंधित प्रावधानों का अर्थ लगाते समय परोपकारी निर्माण लागू किया गया है। [140 - ए; 141-ए-एफ]

3.2 . यह मानते हुए कि संशोधन अधिनियम लोगों की भलाई के लिए है, उपरोक्त स्थितियों की उपस्थिति ऐसे नियम को लागू करने के लिए नहीं पाई जाती है।

संशोधित श्याम सुंदर v द्वारा प्रस्तुत अधिनियम की धारा 15 को प्रतिस्थापित करते हुए।

राम कुमार

121

इसमें उपयोग किए जाने वाले सरल और सरल हैं और इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। शब्द हैं। खंड में उपयोग एक से अधिक अर्थ को जन्म नहीं देता है। अगर यह आयोजित किया जाता है

कि संशोधन अधिनियम पूर्वव्यापी है, तब न्यायालय होगा

उन शब्दों को जोड़कर अधिनियम को फिर से लागू करना जो इसमें नहीं पाए जाते हैं

अधिनियम में या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से संशोधन करना और यह

संशोधन अधिनियम की भावना के साथ हिंसा करने के बराबर है। इनके लिए

कारण, परोपकारी निर्माण के नियम का अनुप्रयोग पूरी तरह से है अधिनियम की प्रतिस्थापित धारा 15 का अर्थ लगाते समय लागू नहीं होता है।

[1

41 - जी-एच; 142-ए]

3.3 . निर्माण का ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक लाभकारी कानून हो

संचालन में हमेशा पूर्वव्यापी, भले ही ऐसा कानून या तो स्पष्ट रूप से हो या आवश्यक इरादे से पूर्वव्यापी नहीं बनाया जाता है। [142 - बी, सी]

3.4 . पूर्व-अधिकार का अधिकार एक कमजोर अधिकार हो सकता है लेकिन फिर भी

अधिकार कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसके भीतर पराजित होने की अनुमति दी जा सकती है

संभावित जब तक कि स्पष्ट रूप से या आवश्यक रूप से पूर्वव्यापी नहीं किया जाता है इरादा। [142 - एफ, जी]

मोती राम बनाम। सूरज भान और ओआरएस। , [1960] 2 एस. सी. आर. 896 पर भरोसा किया।

रफीक्वेनेसा वी। लाल बहादुर छेत्री (मृत) एलआरएस के माध्यम से। और ओआरएस। , [1964]

6 एस. सी. आर. 876 और एच. शिव राव और अन्र। वी. सेलेलिया परेरा और ओआरएस। , [1987] 1 एससीसी 258, विशिष्ट।

4.1 : आम तौर पर जब कोई अधिनियम पिछले कानून की घोषणा करता है, तो इसकी आवश्यकता होती है

पूर्वगामी प्रभाव दिया जाए। एक घोषणात्मक कानून का कार्य आपूर्ति करना है।

एक चूक या पिछले क़ानून की व्याख्या और जब ऐसा कोई अधिनियम पारित किया जाता है, तो

यह तब लागू होता है जब पिछला अधिनियम पारित किया गया था। कानून बनाने की विधायी शक्ति में यह घोषित करने की शक्ति शामिल है कि पिछली कानून क्या थी और जब ऐसा घोषणात्मक अधिनियम हमेशा पारित किया जाता है तो इसे पूर्वव्यापी माना जाता है। किसी अधिनियम में 'घोषणा' शब्द के उपयोग की अनुपस्थिति, जो यह बताती है कि पहले कानून क्या था, एक घोषणात्मक अधिनियम प्रतीत नहीं हो सकता है, लेकिन यदि न्यायालय किसी अधिनियम को घोषणात्मक या व्याख्यात्मक पाता है तो इसे पूर्वव्यापी के रूप में माना जाना चाहिए। इसके विपरीत जहां कोई क़ानून 'घोषणात्मक' शब्द का उपयोग करता है, इस प्रकार उपयोग किए गए शब्द यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं कि क़ानून एक घोषणात्मक अधिनियम है क्योंकि शब्दों का उपयोग नए कानून को लागू करने के लिए किया जा सकता है। घोषणात्मक या व्याख्यात्मक अधिनियम का कार्य एक स्पष्ट चूक प्रदान करना या पिछले अधिनियम के अर्थ के बारे में संदेह को दूर करना है और ऐसा अधिनियम पिछले अधिनियम के पारित होने की तारीख से प्रभावी होता है। [143 - जी-एच; 144-ए, बी] 122

केशवलाल जेठालाल शाह बनाम। मोहनलाल भगवानदास और अन्र। , [1968] 3

एस. सी. आर. 623 और आर. राजगोपाल रेड्डी (मृत) एल. आर. एस. और ओआरएस। वी. पद्मिनी

एलआरएस द्वारा चंद्रशेखरन (मृत)। , [1995] 2 एस. सी. सी. 630, पर भरोसा किया।

मिथिलेश कुमारी और अन्र। वी. प्रेम बिहारी खरे, [1989] 2 एस. सी. सी. 95,

संदर्भित किया गया।

एक क़ानून पर क्रेज़, 7 वां संस्करण; जी. पी. सिंह-वैधानिक सिद्धांतों पर

व्याख्या, संदर्भित।

4.2 . संशोधन अधिनियम की धारा 15 को या तो स्पष्ट रूप से या द्वारा प्रतिस्थापित किया गया

एक चूक प्रदान करने या एक संदेह को दूर करने के लिए आवश्यक निहितार्थ

मूल अधिनियम की धारा 15 सटीक, स्पष्ट और सरल थी। वहाँ कोई नहीं था। उसमें अस्पष्टता। माता-पिता की धारा 15 में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ

संशोधन अधिनियम द्वारा आपूर्ति की आवश्यकता थी। इसके अलावा, संशोधन अधिनियम या तो स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से पूर्वव्यापी होने का इरादा नहीं था और

अतः 1995 का संशोधन अधिनियम एक घोषणात्मक अधिनियम नहीं है और इसलिए इसका कोई प्रावधान नहीं है।

पूर्वव्यापी संचालन। [145 - एच, 146-ए-बी।

5.1 . संशोधन अधिनियम के लागू होने की संभावना होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है

पूर्व-अभियोग वाद और अपीलीय न्यायालय को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। या संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्थापित धारा 15 को प्रभावी बनाना।

1993 .

पंजाब और हरियाणा के 9.12.92 दिनांकित निर्णय और आदेश से

1991 के आर. एस. ए. सं. 647 में उच्च न्यायालय।

के साथ

सी. ए. सं. 4945-46 , 4949 , 4947 , 4948/2001 , 11868 , 11558/96 , 416 ,

417 , 668 , 5083-84 / 97 , 4390 , 4377-78 1990 से।

पी. सी. जैन, डॉ. राजीव धवन, के. राममूर्ति, एस. के. बग्गा, बी. एस. मलिक,

एम. एन. कृष्णमणि, बबीर सिंह गुप्ता, के. बी. रोहतगी, सुश्री अपर्णा रोहतगी जैन, जेल पाल, बृजेंद्र चाहर, सुश्री ज्योति चाहर, विनय गर्ग, महेश कसाना, जसबिर एस. मलिक, एम. एस. दहिया, एस. एम. हुड्डा, बी. एस. मोर, श्रीमती सुरेस्ता बग्गा, 123

श्याम सुंदर बनाम। राम कुमार [वी. एन. खरे, जे.]

शिव सागर तिवारी, हरिंदर एम. सिंह, अतुल कुमार, रणबीर सिंह यादव,

आशुतोष कुमार, राजेश के. शर्मा, श्रीमती शालू शर्मा, सद्भावना इंदिवर, श्रीमती अंजनी अय्यगारी, के. जी. भगत, विनीत भगत, आर. के. अग्निहोत्री, सुश्री कुसुम

चौधरी, ऋषि मल्होत्रा, प्रेम मल्होत्रा, आर. एस. कटारिया, बलराज दीवान, एस. के. मेहता, अजय मजीठिया, एस. बी. उपाध्याय, घन श्याम वशिष्ठ, मनोज स्वरूप,

प्रदीप सिंह, हीरेन दासन, एस. एस. वत्स, सर्वेश बिसारिया, के. आर. नागराजा, विवेक

सिब्बल, श्रीमती नरेश बख्शी, आर. सी. वर्मा, विवेक विश्नोई, सुश्री किरण कपूर, नीरज कुमार जैन, सुश्री आभा आर. शर्मा, शीला गोयल और सुश्री एस. जनानी उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वी. एन. खरे, जे. लीव मंजूर।

" हरियाणा सरकार द्वारा प्रतिस्थापित धारा 15 का क्या प्रभाव पड़ता है?

मूल अधिनियम में संशोधन अधिनियम, 1995 (जिसे इसके बाद संशोधन अधिनियम 1995 के रूप में संदर्भित किया गया है) अर्थात पंजाब पूर्व-प्रवर्तन अधिनियम (जिसे इसके बाद के रूप में संदर्भित किया गया है) मूल अधिनियम) जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू होता है, जिसके तहत उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ दायर अपील के लंबित रहने के दौरान एक सह-हिस्सेदार का बिक्री को पूर्व-खाली करने का अधिकार छीन लिया गया है, जिसमें निचली अदालत द्वारा पूर्व-प्रवर्तन मुकदमे में पारित डिक्री की पुष्टि की गई है।

यही वह संक्षिप्त प्रश्न है जिसका उत्तर हमें इस समूह में देना है।

अपीलों की जो हमारे समक्ष संदर्भ पर आई हैं।

जब सिविल अपील सं. 4680/93 पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई

इस न्यायालय की पीठ ने मूल अधिनियम में 1995 में किए गए संशोधन के प्रभाव के प्रश्न पर पाया कि इस न्यायालय की दो तीन न्यायाधीशों की पीठ, जो कि दीदार सिंह आदि हैं, के निर्णयों में लिए गए विचार में विरोधाभास है। वी. एलआरएस द्वारा इशर सिंह (मृत)। आदि। , [1995] 1 पैमाना 1 (जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पूर्व-प्रवर्तन के लिए एक सूट में, पूर्व-खाली करने वाले को साबित करना होगा

प्रथम न्यायालय की डिक्री की तारीख तक पूर्व-खाली करने का उसका अधिकार और वाद के निर्णय की तारीख के बाद और अपील के लंबित होने के दौरान कानून में किसी भी अधिकार या बाद में परिवर्तन का

नुकसान प्रथम न्यायालय की डिक्री को प्रभावित नहीं करेगा) और रामजीलाल और अन्य। आदि वी। घिसा राम आदि। जे. टी. (1996) 2 एस. सी. 649 (जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि अपील वाद की निरंतरता होने के कारण, पूर्व-समावेशन का दावा करने का अधिकार उस तारीख को उपलब्ध होना चाहिए जब डिक्री बनाई जाती है और अंततः इसकी पुष्टि की जानी है या अपील के निपटारे के समय इसे संशोधित करने की आवश्यकता है, और चूंकि संशोधन अधिनियम इस अवधि के दौरान लागू हुआ था।

अपील की लंबितता, वादी का अधिकार और उपचार समाप्त हो गया 124

और इसके परिणामस्वरूप मुकदमा विफल होना चाहिए)। के बीच संघर्ष को हल करने के लिए पीठ ने दो अलग-अलग पीठों द्वारा दिए गए उपरोक्त दो निर्णयों का उल्लेख किया पाँच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्णय के लिए अपील। यह इस तरह से है, बात हमारे सामने आ गया है।

चूंकि कानून का सामान्य प्रश्न अपीलों के इस समूह में शामिल है, इसलिए हम उन तथ्यों पर ध्यान दिया जाएगा जिन्होंने सिविल अपील संख्या 4680/1993 को जन्म दिया है।

प्रतिवादी/अपीलकर्ताओं ने इसमें 54 कनाल की भूमि खरीदी, रिठाल फोगाट गाँव में स्थित है, जो खेवत्स संख्या की भूमि का आधा हिस्सा है। 204 , 205 और 206,108 कनाल मापने के लिए रु। 84,000 से विक्रेताओं अर्थात। , भारपाई, छोटा और प्यारी-भगवान की बेटियाँ वीडियो सेल दिनांकित विलेख 17.7.1985। वादी/उत्तरदाताओं ने यहाँ वरीयता का दावा किया जमीन पर प्रतिवादी-अपीलार्थियों के पक्ष में बिक्री को पूर्व-खाली करने का अधिकार कि वे उप-न्यायाधीश के समक्ष रखे गए दीवानी मुकदमे के माध्यम से सह-भागीदार हैं, 1 सेंट क्लास, गोहाना। उक्त मुकदमे में मुद्दे तैयार किए गए और निचली अदालत ने वादी/उत्तरदाताओं के पक्ष में सभी मुद्दों का निर्णय लिया और परिणामस्वरूप 30.5.1990 पर मुकदमा तय किया गया था। उत्तरदाताओं के पारित होने के बाद पहली बार की अदालत द्वारा डिक्री ने खरीद के पैसे को इस रूप में जमा किया आदेश 20 नियम 14 सी. पी. सी. के तहत आवश्यक है। अपीलार्थियों द्वारा पसंद की गई अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष और उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील खारिज कर दिए गए और निचली अदालत के आदेश की पुष्टि की गई। याचिकाकर्ताओं इसके बाद विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से इस अपील को प्राथमिकता दी गई। इस दौरान मूल अधिनियम की धारा 15 (1) (बी), जिसके आधार पर अपील लंबित है।

वाद वादी/उत्तरदाताओं द्वारा दायर किया गया था और इसमें संशोधन किया गया था

नई धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है जिसके तहत सह-भागीदार का पूर्व-खाली करने का अधिकार है। एक बिक्री छीन ली गई। अधिनियम की प्रतिस्थापित धारा 15 निम्नानुसार है:

" 15. किरायेदार में निहित होने का पूर्व-अधिकार। पूर्व-समावेशन का अधिकार

कृषि भूमि और गाँव की अचल संपत्ति की बिक्री के संबंध में

किरायेदार में निहित होगा जो वर्डर या विक्रेताओं की किरायेदारी के तहत रखता है

बेची गई भूमि या संपत्ति या उसके किसी हिस्से का।

अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान वकील,

रामजीलाल बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। घिसा राम (ऊपर) और संशोधन

1995 के अधिनियम में आग्रह किया गया कि अधिनियम की प्रतिस्थापित धारा 15 द्वारा सह-हिस्सेदार के पूर्व-खाली बिक्री के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, अपील मुकदमे की निरंतरता होने के कारण, यह न्यायालय विधायी परिवर्तनों को ध्यान में रखने में सक्षम है और उस स्थिति में वादी-प्रतिवादी मुकदमा विफल होना चाहिए। दूसरा यह आग्रह किया गया था कि संशोधन अधिनियम प्रकृति में घोषणात्मक होने के कारण, इसका पूर्वव्यापी प्रभाव पड़ता है और इसके परिणामस्वरूप, श्याम सुंदर v की तिथि पर सह-भागीदार को जो भी अधिकार था।

राम कुमार [वी. एन. खरे, जे.]

125

प्रथम दृष्टांत न्यायालय की डिक्री संशोधन के बाद समाप्त हो गई अधिनियम लागू हुआ। तीसरा तर्क यह था कि किसी भी स्थिति में, संशोधन

अधिनियम नागरिकों की सामान्य भलाई के लिए पारित लाभकारी कानून होने के कारण, यह न्यायालय जबकि नई प्रतिस्थापित धारा 15 का अर्थ लगाने के लिए नियम लागू करना आवश्यक है -

परोपकारी निर्माण और उस स्थिति में अधिनियम में संशोधन पूर्वव्यापी होगा।

ऑपरेशन। दूसरी ओर उत्तरदाताओं के वकील का तर्क है कि

पूर्व-समावेशन के लिए एक मुकदमे में दावेदार को तारीख को अपना अधिकार साबित करना होता है

प्रथम न्यायालय की डिक्री और एक अधिनियम द्वारा डिक्री की तारीख के बाद अधिकार की हानि उसके नियंत्रण से परे या बाद में कानून में परिवर्तन ने उसके दावे को प्रभावित नहीं किया

यह मानते हुए कि अपील मुकदमे की निरंतरता है, संशोधन अधिनियम जिसका कोई पूर्वव्यापी संचालन नहीं है, के आदेश को प्रभावित नहीं करता है

प्रथम उदाहरण न्यायालय। यह भी आग्रह किया गया कि आदेश के प्रावधानों को देखते हुए 20 नियम 14 सी. पी. सी. संपत्ति का अधिकार पहले ही उसे दे दिया गया था।

क्रय राशि जमा करने पर दावेदार और इसलिए, संशोधन अधिनियम दावेदार द्वारा अर्जित अधिकार को प्रभावित नहीं करता है।

पक्षकारसभक विद्वान वकीलक तर्क पर ओ प्रश्न जे -

विचार के लिए निम्नलिखित हैं - (i) क्या अपील की निरंतरता है

मुकदमा, मूल अधिनियम की धारा 15 में संशोधन जिसके द्वारा एक

अपील के लंबित रहने के दौरान एक बिक्री को पूर्व-खाली करने के लिए सह-भागीदार को हटा दिया गया है, जो मुकदमे की रखरखाव क्षमता और एक कंपनी के अधिकारों को प्रभावित करेगा।

हिस्सेदार और (ii) क्या संशोधन अधिनियम का पूर्वव्यापी संचालन है ताकि मुकदमेबाजी में पक्षों के अधिकारों को प्रभावित किया जा सके।

पक्षकारों के लिए उनके तर्कों के समर्थन में विद्वान वकील ने भरोसा किया

प्रिवी काउंसिल, संघीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की संख्या के आधार पर, यह

न्यायालय और विभिन्न अन्य उच्च न्यायालय। इन निर्णयों में व्यक्त किए गए विचारों की पूरी तस्वीर रखने और उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, बार में उद्धृत निर्णयों को वर्गीकृत करना उचित है जिन्हें इसके बाद निर्णयों की पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणियों के रूप में संदर्भित किया जाएगा। निर्णयों की पहली श्रेणी वे हैं जिनमें व्यक्त कानून का दृष्टिकोण यह है कि

प्री-एम्प्शन के लिए सूट में, प्री-एम्प्टर को प्री-एम्पेशन का अधिकार होना चाहिए।

बिक्री की तारीख से लेकर प्रथम न्यायालय की डिक्री की तारीख तक का अधिकार और डिक्री की तारीख के बाद उस अधिकार का नुकसान या तो स्वयं के अधिनियम द्वारा, या उसके नियंत्रण से परे किसी कार्य द्वारा या कानून में किसी भी बाद के परिवर्तन द्वारा जो कि न्यायालय की पहली बार की डिक्री के खिलाफ दायर अपील के लंबित रहने के दौरान संभावित रूप से लागू होता है, पूर्ववर्ती के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा। निर्णयों की दूसरी श्रेणी उन मामलों से संबंधित है जहां एक पूर्ववर्ती का अधिकार छीन लिया गया था 126

एस सी आर।

प्रथम न्यायालय की डिक्री की तारीख के बाद और अपील के लंबित रहने के दौरान

सांविधिक अधिनियमन द्वारा जिसका पूर्व सक्रिय संचालन था। ऐसे मामलों में यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलीय न्यायालय विधायी को ध्यान में रखने के लिए सक्षम है

परिवर्तन जो पूर्वव्यापी हैं और तदनुसार पक्षों के अधिकारों को प्रभावित करते हैं

मुकदमे के लिए। तीसरी श्रेणी के मामलों में निर्णय वे होते हैं जहाँ

अभिनिर्धारित किया गया है कि अपील मुकदमे की निरंतरता है, पूर्व-खाली करने का अधिकार

बिक्री उस तारीख को उपलब्ध होनी चाहिए जब डिक्री दी जाती है और अंत में

अपील के लंबित रहने के दौरान विधायी परिवर्तनों द्वारा अधिकार के नुकसान का मामला, प्री-एम्प्शन के लिए सूट विफल होना चाहिए।

निर्णयों की पहली श्रेणी में पहला मामला इलाहाबाद का निर्णय है।

सकीना बीबी बनाम में उच्च न्यायालय। अमीरन और ओआरएस। , [1888] आई. एल. आर. 10 इलाहाबाद 472

जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह देखने के लिए एक अपील न्यायालय की आवश्यकता है कि क्या था

डिक्री जिसे पहली बार की अदालत को पारित करना चाहिए था, और यदि अदालत पहली बार में दावे को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया है, वादी को पूर्वाग्रह नहीं किया जा सकता है

उसके हिस्से को बाद में एक डिक्री के निष्पादन में बेचा गया था

एक और सूट। इस तरह की बिक्री पूर्ववर्ती के रखरखाव के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

ऐसा पाया जाना जो डिक्री की तारीख को मौजूद था और अपील के लंबित रहने के दौरान निष्पादन कार्यवाही में भूमि की कोई भी बाद की बिक्री सूट की रखरखाव क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। बलदेव मिसिर बनाम। राम लगान शुकुल, (1923) आई. एल. आर. (45) इलाहाबाद 709, यह निर्धारित किया गया था कि यह देखा जाना चाहिए कि क्या पूर्व-खाली करने वाले को डिक्री की तारीख पर अधिकार है।

पहला न्यायालय। अपील के लंबित रहने के दौरान अधिकार का कोई भी बाद में परिवर्तन पूर्व-खाली करने वाले के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा। हंस नाथ और ओआरएस में। वी. राघौ प्रसाद सिंह,

[59 द लॉ रिपोर्ट्स (इंडियन अपील्स) 138], बलदेव मिसिर बनाम में निर्णय के बाद प्रिवी काउंसिल। राम लगान शुकुल (ऊपर) ने माना कि एक पूर्व-खाली करने वाले के दावे को उसकी वरीयता खोने से हराया जा सकता है

बिक्री के बाद और मुकदमे के निर्णय से पहले किसी भी समय पूर्व-खाली करने की योग्यता। संक्षेप में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक पूर्व-खाली करने वाले को बिक्री की तारीख, मुकदमा दायर करने की तारीख और निचली अदालत द्वारा डिक्री पारित करने की तारीख को पहले से खाली करने का अधिकार होना चाहिए। प्रिवी काउंसिल का यह निर्णय यह तत्कालीन आगरा प्रांत में प्रचलित पूर्व-अधिग्रहण के अधिकार से संबंधित है, लेकिन इसका पालन किया गया था और पहले तत्कालीन अविभाजित पंजाब में लागू किया गया था।

माधो सिंह बनाम में लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा देश का विभाजन। लेफ्टिनेंट जेम्स आर. आर. एस. किनर, (1942) आई. एल. आर. (23) लाहौर 155 और ज़हूर दीन और अन्र। वी. जाला! दीन नूर मोहम्मद और ओआरएस। , (1944) आईएलआर (25) लाहौर 443]। दोनों मामलों में, लाहौर उच्च न्यायालय की दो पूर्ण पीठों ने माना कि यह श्याम सुंदर बनाम नहीं है।

राम कुमार [वी. एन. खरे, जे.]

127

उस तारीख को बढ़ाना संभव है जिसके द्वारा एक पूर्व-प्रत्यर्पण सूट में एक विक्रेता कर सकता है

पहली अदालत द्वारा मुकदमे की मुकदमेबाजी की तारीख से आगे उसकी स्थिति में सुधार करना। उदाहरण और इसलिए, वह विचाराधीनता के दौरान अपनी स्थिति में सुधार करके नहीं कर सकता है।

अपील पूर्व-खाली करने वाले के अधिकार को पराजित करती है। रामजी लाल और अन्र में। वी. पंजाब राज्य और अन्य।, (1966) आई. एल. आर. 19 (2) पंजाब 125 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्री-एम्प्टर के पास बिक्री की तारीख को प्री-एम्प्टी करने की योग्यता होनी चाहिए।

वाद की स्थापना की तारीख और विचारण न्यायालय की डिक्री की तारीख को। द. प्रीएम्प्टर को डिक्री की तारीख को प्री-एम्प्टी करने की अपनी योग्यता बनाए रखनी चाहिए।

केवल प्रथम न्यायालय का और बाद में प्रीएम्प्टर द्वारा योग्यता का कोई नुकसान

अपने स्वयं के कार्य से या अपने नियंत्रण से परे किसी कार्य से प्रभावित नहीं होता है

सूट की रखरखाव क्षमता। भगवान दास (डी) में एलआरएस द्वारा। और ओआरएस। वी. चेत।

राम, [1971] 2 एस. सी. आर. 640 इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि

अधिवेशक को अधिवेतन द्वारा अधिकार के लिए डिक्री की तारीख तक पूर्व-खाली करने की अपनी योग्यता बनाए रखनी चाहिए। इस निर्णय ने पूर्ण के निर्णय को मंजूरी दी

रामजी लाल बनाम में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दी गई पीठ। की स्थिति

पंजाब, (ऊपर)। रिखी राम और अन्र में। वी. राम कुमार और ओआरएस।, [1975] 2 एस. सी. सी. 318 इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने दोहराया कि एक पूर्व-रिक्तता जो बिक्री की तारीख को बिक्री को पूर्व-खाली करने के अधिकार का दावा करता है, उसके पास डिक्री की तारीख तक वह अधिकार बना रहना चाहिए। यदि दावेदार उस अधिकार को खो देता है

डिक्री के पारित होने से पहले, न्यायालय द्वारा पूर्व-प्रवर्तन के लिए कोई डिक्री नहीं दी जा सकती है, भले ही उसे मुकदमे की तारीख को ऐसा अधिकार प्राप्त हो। दीदार सिंह बनाम। इशर सिंह (ऊपर) इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने यह निर्धारित किया कि पूर्व-समावेशन के लिए एक मुकदमे में, दावेदार को यह साबित करना होगा कि उसका पूर्व-रिक्त होने का अधिकार प्रथम न्यायालय की डिक्री की तारीख तक मौजूद है और नुकसान

डिक्री की तारीख के ठीक बाद अपने नियंत्रण से परे किसी कार्य द्वारा या विचारण न्यायालय की डिक्री के खिलाफ अपील के लंबित रहने के दौरान वैधानिक हस्तक्षेप द्वारा दावेदार को पहले से ही प्रयोग किए गए और घोषित किए गए पूर्व अधिनिर्णय के अपने दावे को बनाए रखने के लिए अयोग्य नहीं ठहराएगा। इस मामले में फिर से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा रामजी लाल बनाम. पंजाब राज्य (ऊपर) को मंजूरी दी गई।

प्रथम श्रेणी में निर्दिष्ट उपरोक्त निर्णयों का विश्लेषण

निर्णय, उभरने वाले कानूनी सिद्धांत ये हैं:

1 . पूर्व-खाली करने वाले को तारीख को पूर्व-खाली करने का अधिकार होना चाहिए

बिक्री, मुकदमा दायर करने की तारीख और पारित होने की तारीख को

केवल पहली बार के न्यायालय द्वारा डिक्री।

2 . पूर्व-खाली करने वाला जो बिक्री को पूर्व-खाली करने के अधिकार का दावा करता है

बिक्री की तारीख से यह साबित होना चाहिए कि ऐसा अधिकार तब तक बना रहा जब तक कि

प्रथम न्यायालय की डिक्री का पारित होना। यदि दावेदार 128 खो देता है

एस सी आर।

वह अधिकार या विक्रेता वाद के निर्णय से पहले दावेदार के अधिकार के बराबर या उससे ऊपर अपने अधिकार में सुधार करता है।

इमप्शन को विफल होना चाहिए।

3 . एक पूर्व-मुक्तिदाता जिसे वाद की स्थापना की तारीख और डिक्री पारित होने की तारीख को बिक्री को पूर्ववत करने का अधिकार है, पहले न्यायालय की डिक्री के बाद ऐसे अधिकार का नुकसान होगा।

पूर्व-प्रवर्तन के लिए मुक़दमे के उसके अधिकार या रखरखाव को प्रभावित नहीं करता है।

4 . एक पूर्व-रिक्तकर्ता जिसने बिक्री की तारीख को, मुकदमा दायर करने की तारीख को और प्रथम न्यायालय द्वारा डिक्री पारित होने की तारीख को अपना अधिकार साबित करने के बाद, प्रथम दृष्टांत न्यायालय द्वारा पूर्व-प्रवर्तन के लिए एक डिक्री प्राप्त की है, ऐसे अधिकार को इस प्रकार नहीं लिया जा सकता है

इसके विरुद्ध दायर अपील के लंबित रहने के दौरान बाद का कानून

डिक्री जब तक कि इस तरह के कानून का पूर्वव्यापी संचालन न हो।

निर्णयों की दूसरी श्रेणी पर आते हुए यह ध्यान दिया जा सकता है कि जबकि

निर्णयों की पहली श्रेणी में निर्धारित कानून का दृष्टिकोण,

लच्मेश्वर प्रसाद शुकुल और अन्य के मामले में संघीय न्यायालय। वी. केसर

लाल चौधरी और ओआरएस। , ए. आई. आर. (1941) फेडरल कोर्ट 5 व्याख्या करते हुए

बिहार धन-ऋणदाता अधिनियम, 1939 की धारा 7 जो पूर्वव्यापी पाई गई थी।

अभिनिर्धारित किया कि एक बार उच्च न्यायालय की डिक्री के खिलाफ अपील की गई थी, मामला फिर से विचाराधीन हो जाता है और उसके बाद अपीलीय न्यायालय ने

पूरे मामले का, हालांकि कुछ उद्देश्यों के लिए, उदाहरण के लिए निष्पादन, डिक्री इसे अंतिम माना जाता था और नीचे के न्यायालयों ने अधिकार क्षेत्र बनाए रखा। सिद्धांत

संघीय न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को अधिनियम के उन प्रावधानों के संदर्भ में समझना होगा जिनकी विद्वान न्यायाधीश व्याख्या कर रहे थे। लछमीश्वर प्रसाद शुकुल और ओरस में लिया गया

दृष्टिकोण। वी. राम लाल बनाम में केशवर लाल चौधरी (ऊपर) का अनुसरण किया गया था। राजा राम और अन्र। , [1960] पंजाब लॉ रिपोर्टर 291। उच्च न्यायालय का विचार था कि अपील मूल कार्यवाही की निरंतरता और वाद की पुनः सुनवाई होने के कारण, संशोधन अधिनियम को पूर्वव्यापी होने के कारण विचार में लिया जाना चाहिए और न केवल दायर किए गए नए वाद या लंबित वाद में बल्कि उन मामलों में भी प्रभावी होना चाहिए जहां अपील लंबित है और निर्णय नहीं लिया गया है। शून्य में, उच्च न्यायालय का विचार था कि अपील एक मुकदमे की निरंतरता होने के कारण, अपीलीय न्यायालय इस पर विचार करने का हकदार है।

कानून में परिवर्तन को ध्यान में रखें जो पूर्वव्यापी है। राम लाल बनाम में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का निर्णय। राजा राम (उपरोक्त) को राम सरूप बनाम में अनुमोदित किया गया था। मुंशी और ओआरएस। , [1963] 3 एससीआर 858। इसकी एक संविधान पीठ

राम सरूप मामले (उपर्युक्त) में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 1960 के संशोधन अधिनियम 10 की धारा 31 पूर्वव्यापी होने के कारण, संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले अर्जित बिक्री को पूर्व-खाली करने का अधिकार विफल हो गया।

पीठ ने यह भी नोट किया और समझाया कि लछमीश्वर प्रसाद शुकुल बनाम।

केसर लाल, (ऊपर), संघीय न्यायालय धारा 7 का अर्थ लगा रहा था

बिहार धन-ऋणदाता अधिनियम जिसका पूर्वव्यापी संचालन था।

राम सरूप बनाम में निर्णय। मुंशी (सुप्रा) के बाद दूसरा आया।

अमीर सिंह और अन्र में इस न्यायालय की संविधान पीठ। वी. राम सिंह और

ओआरएस। , [1963] 3 एस. सी. आर. 884 जिसमें, यह न्यायालय धारा 31 की व्याख्या करते हुए पंजाब संशोधन अधिनियम 1960 द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन अधिनियम ने दोहराया कि पूर्वव्यापी

धारा 31 के प्रवर्तन में अनिवार्य रूप से प्रभाव दिया जाना शामिल है -

अपीलीय न्यायालय द्वारा संशोधित धारा 15 के मूल प्रावधान, चाहे

उसके समक्ष अपील एक पूर्व-अनुमति देने वाली डिक्री के खिलाफ है या एक

उस राहत को अस्वीकार करना।

दूसरी श्रेणी की समीक्षा पर उभरने वाली कानूनी स्थिति

निर्णय यह है कि अपील अपीलीय न्यायालय के मुकदमे की निरंतरता है

कानून में किसी भी परिवर्तन को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है जिसका पूर्वव्यापी प्रभाव है।

अब हम ऊपर उद्धृत निर्णयों की तीसरी श्रेणी पर ध्यान देंगे।

बार। इस श्रेणी के मामलों में पहला निर्णय करण में लिया गया है।

सिंह और ओआरएस। वी. भगवान सिंह, (मृत) एल. आर. और और अन्य द्वारा। , [1996] 7 एससीसी

559 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक अपील मुकदमे की निरंतरता है,

पूर्व-अभिग्रहण का दावा करने का अधिकार उस तारीख को उपलब्ध होना चाहिए जब डिक्री लागू होती है।

अंत में पुष्टि की जानी है और निपटान के समय इसे संशोधित करने की आवश्यकता है अपील और तब से प्रतिस्थापित अधिनियम की धारा 15 के दौरान लागू हुई

अपील की विचाराधीनता, बचावकर्ता का अधिकार और उपचार खड़ा था

बुझा दिया। इस निर्णय का पालन रामजीलाल बनाम में किया गया था। घिसा राम (ऊपर) जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि तब से प्रतिस्थापित धारा 15 को संशोधन द्वारा प्रस्तुत किया गया है -

1995 का अधिनियम अपील के लंबित रहने के दौरान लागू हुआ जो मुकदमे की निरंतरता है, वादी का अधिकार और उपचार समाप्त हो गया।

और जिसके परिणामस्वरूप पूर्व-प्रवर्तन के लिए मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं था।

उपरोक्त निर्णयों से जो कानूनी सिद्धांत निकलता है, वह यह है कि

एक अपील मुकदमे की निरंतरता होने के कारण, पूर्व-खाली करने का अधिकार उस तारीख को उपलब्ध होना चाहिए जब डिक्री बनाई जाती है और अंततः इसकी पुष्टि की जानी है या अपील के निपटारे के समय इसे संशोधित करने की आवश्यकता है और जहां वादी का अधिकार और उपचार अपील के लंबित रहने के दौरान वैधानिक रूप से छीन लिया गया है, तो मुकदमा विफल होना चाहिए।

पक्षों के वकील को सुनने के बाद और ध्यान से अंदर चला गया

बार में उद्धृत निर्णय हम निर्णयों की पहली और दूसरी श्रेणियों में व्यक्त कानून के बयान के साथ सम्मानजनक सहमति में हैं। लेकिन हम 130

तीसरी श्रेणी के निर्णयों के साथ हमारी असहमति व्यक्त करने के लिए खेद है इसके बाद बताए गए कारणों के लिए निर्णय।

आधुनिक समय में, कानूनों के आधार पर पूर्व-प्रवर्तन का अधिकार बहुत अधिक है

एक बदनाम कानून। इन अपीलों की सुनवाई के दौरान ऐसे अधिकार दिए गए हैं - सामंती, पुरातन और पुराने आदि के रूप में वर्णित। लेकिन इसकी उत्पत्ति

प्रथा पर आधारित था और बाद में संहिताबद्ध किया गया था आवश्यकता से बाहर फिर ग्राम समुदाय और समाज को इसके संरक्षण, अखंडता और

शांति और सुरक्षा बनाए रखना। परिवर्तित परिस्थितियों में, पूर्व का अधिकार

इमप्शन को आउटमोडेड कहा जा सकता है, लेकिन जब तक इसे वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है, यह

किसी भी अन्य कानून के समान व्यवहार किया जाना चाहिए। का अधिकार सह-हिस्सेदार का पूर्व-अधिग्रहण भूमि से जुड़ी संपत्ति की घटना है।

स्वयं। यह भूमि के साथ किसी प्रकार का बोझ है जो हो सकता है

भूमि के सह-मालिक द्वारा या उसके विरुद्ध लागू किया गया। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य

परिवार के स्वामित्व या संपत्ति में अजनबी की घुसपैठ। के तहत एक सह-भागीदार पूर्व-प्रवर्तन के कानून को अजनबी के स्थान पर खुद को प्रतिस्थापित करने का अधिकार है

इस तरह का हस्तांतरण और इस तरह से अजनबी को होल्डिंग प्राप्त करने से रोकता है एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पूर्व-प्रवर्तन का कानून प्रचलित है। वर्तमान में ऐसा अधिकार हो सकता है -

यह प्राचीन, सामंती और आधुनिक के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह लगभग दो शताब्दियों तक या तो प्रथा या वैधानिक कानून पर आधारित कानून था। यह इस पृष्ठभूमि में है कि वैधानिक कानून के तहत पूर्व-समावेशन के अधिकार को अनिवार्य माना गया है न कि केवल विवेकाधीन। न्यायालय के पास डिक्री देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है

जहां किसी अन्य सह-हिस्सेदार द्वारा किसी संपत्ति की बिक्री की जाती है। और इस कारण से न्यायालयों ने लगातार यह विचार रखा है कि जहां किसी सह-हिस्सेदार द्वारा स्वामित्व या संपत्ति की बिक्री होती है, वहां पूर्व-अधिनिर्णय के अधिकार का जल्द से जल्द निपटारा किया जाना आवश्यक है, या तो पूर्व-अधिनिर्णयकर्ता द्वारा बिक्री की तारीख को, मुकदमा दायर करने की तारीख को, और पहली बार के

न्यायालय की डिक्री की तारीख को या विक्रेता द्वारा पूर्व-अधिनिर्णय के लिए मुकदमे के निर्णय तक अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए अपनी योग्यता साबित करने पर और पूर्व-अधिनिर्णयकर्ता या विक्रेता द्वारा पूर्व-अधिनिर्णयकर्ता के अधिकार के बराबर या उससे अधिक अपनी स्थिति में सुधार करने की योग्यता के किसी भी नुकसान का कोई परिणाम नहीं है। ज़हूर दीन बनाम। लाहौर उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ जलाल दीन (ऊपर) ने पक्षों के अधिकारों के जल्द से जल्द निपटारे की आवश्यकता व्यक्त करते हुए इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

" यह आवश्यक प्रतीत होता है कि किसी स्तर पर एक रेखा खींची जानी चाहिए।

जब एक पूर्व-खाली करने वाले और एक विक्रेता के बीच की दौड़ समाप्त होनी चाहिए और 131 की तारीख का प्रसिद्ध स्थलचिह्न होने के बाद

श्याम सुंदर "। राम कुमार [वी. एन. खरे, जे.]

अब अनिवार्य रूप से पीछे की बिक्री-सबसे दूर की सीमा जो दी जा सकती है एक विक्रेता के लिए मुकदमे द्वारा मुकदमे के निर्णय के समय का है

(जोर दिया गया)

अदालत "।

जैसा कि पहले देखा गया है, हंस नाथ बनाम। राघौ प्रसाद सिंह, (ऊपर) प्रिवी

परिषद ने अभिनिर्धारित किया कि प्री-एम्प्शन के लिए सूट बनाए रखने के लिए एक प्री-एम्प्टर की आवश्यकता होती है।

तीन महत्वपूर्ण तिथियों पर अपने अधिकार को साबित करने के लिए। दावेदार को करना होगा

मुकदमे के निर्णय की तारीख पर मौजूद रहता है। लेकिन यह एक बात है इसका कोई परिणाम नहीं होगा कि क्या विचारण न्यायालय वाद का आदेश देता है या खारिज करता है। इसमें है।

प्रिवी काउंसिल और विभिन्न उच्च न्यायालयों का भी सुसंगत दृष्टिकोण रहा है कि

एक पूर्व-खाली करने वाले के पास उस तारीख को बिक्री से पहले खाली करने की योग्यता होनी चाहिए

प्रथम दृष्टांत न्यायालय की डिक्री केवल वाद की रखरखाव के लिए

हालाँकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्री-एम्प्टर बाद में प्री-एम्प्शन का अधिकार खो देता है।

मुकदमे का निर्णय या तो अपने स्वयं के कार्य या प्रतिशोध द्वारा उसकी स्थिति में सुधार

डिक्री के खिलाफ दायर अपील के लंबित रहने के दौरान पूर्व-खाली करने के लिए योग्य

ट्रायल कोर्ट। कानून का यह दृष्टिकोण अधिकार के पीछे के उद्देश्य के अनुरूप है।

एक शताब्दी से अधिक समय तक मैदान पर रहे और जिसके साथ हम हैं सम्मानजनक समझौता, क्योंकि हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है जो हमें राजी कर सके

हम एक विपरीत दृष्टिकोण लेते हैं और तय किए गए कानून को बाधित करते हैं।

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि एक अपील की जा रही है

मुकदमे की निरंतरता, अपीलीय न्यायालय को नोटिस करने और विचार करने की आवश्यकता है बाद की घटना, अर्थात्, पूर्व-खाली करने वाले द्वारा योग्यता का नुकसान

अपील की विचाराधीनता। वास्तव में, तर्क यह है कि जहां एक सह-भागीदार हार जाता है

अपील के लंबित रहने के दौरान पूर्व-खाली करने का अधिकार पूर्व-खाली करने वाले का मुकदमा विफल होना चाहिए।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ संदर्भों में एक अपील मुकदमे की निरंतरता है और अपीलीय न्यायालय मुकदमे की फिर से सुनवाई कर रहा है, लेकिन इतनी व्यापक अपीलीय शक्ति का उपयोग किसी पूर्व-खाली करने वाले के निहित अधिकार को प्रभावित करने के लिए नहीं किया गया है। यह नहीं है।

इस बात पर विवाद है कि एक दावेदार का विक्रेता की वरीयता में संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार मुकदमे के निर्णय की तारीख तक एक अनुचित अधिकार है, लेकिन यह उसके पक्ष में एक डिक्री पारित होते ही प्रभावी हो जाता है। नियम 14 सी. पी. सी. के आदेश 20 उप-नियम (1) में यह प्रावधान है कि जहां कोई अदालत पूर्व-खाली करने का दावा करती है

संपत्ति की किसी विशेष बिक्री के संबंध में और एक डिक्री धारक ने मुकदमे की लागत के साथ खरीद राशि अदालत में जमा कर दी है, विक्रेता को डिक्री धारक को संपत्ति का कब्जा देने की आवश्यकता होती है और संपत्ति का स्वामित्व दावेदार के पक्ष में हस्तांतरित किया जाता है। उक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, दावेदार द्वारा न्यायालय में खरीद राशि जमा करने पर संपत्ति का अधिकार और अधिकार पूर्व-रिक्तक में निहित हो जाता है और यह निहित अधिकार बन जाता है।

प्री-एम्प्टर का। डिक्री से पहले पूर्व-प्रवर्तन का अधिकार कमजोर हो सकता है लेकिन

जब यह निहित अधिकार बन जाता है, तो इसे केवल ज्ञात तरीके से ही लिया जा सकता है

कानून से। प्री-एम्प्टर या वेंडी अधिग्रहण स्थिति की योग्यता का नुकसान

अपील की विचाराधीनता के दौरान पूर्व-खाली करने के लिए ऊपर को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है

अपील न्यायालय के रूप में न्यायालय मुख्य रूप से की शुद्धता से संबंधित है प्रथम दृष्टांत न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय। जैसा कि पहले देखा जा चुका है कि

एक अपीलीय न्यायालय को बाद की घटना पर विचार करने का अधिकार है।

यथास्थिति, वाद या लिखित कथन में संशोधन की अनुमति देता है, लेकिन कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए संशोधन की अनुमति है और नहीं

बिना किसी उपचार के। इस प्रकार यह केवल वे घटनाएँ हैं जो हुई हैं या पूर्व-प्रवर्तन वाद के निर्णय से पहले पक्षों के अधिकार और जो

विचारण न्यायालय निपटान का हकदार था, केवल इसके द्वारा विचार किया जा सकता है

अपीलीय न्यायालय। हम सकीना बीबी बनाम में निर्णय से अपने दृष्टिकोण का समर्थन पाते हैं। अमीरान (उपर्युक्त) जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

अपील की आवश्यकता केवल यह देखने के लिए थी कि क्या निचली अदालत ने गलत तरीके से खारिज कर दिया था

पूर्व-खाली करने का दावा और यह अप्रासंगिक है कि अपील के लंबित रहने के दौरान भूमि को किसी अन्य मुकदमे में निष्पादन कार्यवाही में बेचा गया था। एक पूर्व में

अभिग्रहण मामला जहां पहली बार अदालत की डिक्री के खिलाफ अपील दायर की जाती है, अपील का दायरा इस सवाल तक सीमित है कि क्या निर्णय लिया गया है।

विचारण न्यायालय का निर्णय सही है या नहीं। यह वह कानूनी स्थिति है जो

एक शताब्दी से अधिक समय से अपील के लंबित रहने के दौरान होने वाली किसी भी बाद की घटना को अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है अन्यथा यह एक पूर्व-रिक्तकर्ता के मामले को विस्थापित कर सकता है।

इसके बाद अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि कानून का दृष्टिकोण (i)

कि एक पूर्व-प्रवर्तन वाद में डिक्री के खिलाफ दायर अपील के लंबित रहने के दौरान होने वाली बाद की घटना या कानून में परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है

अपीलीय न्यायालय और यह कि (ii) अपीलीय न्यायालय द्वारा यह देखने की आवश्यकता है कि क्या निर्णय की तारीख को पक्षकारों के अधिकारों के आधार पर प्रथम दृष्टांत न्यायालय द्वारा पारित डिक्री, लच्मेश्वर प्रसाद शुकुल बनाम मामले में संघीय न्यायालय के निर्णय को देखते हुए अच्छी कानून नहीं रही है। केसर लाल चौधरी (उपर्युक्त) जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि एक अपील मुकदमे की पुनः सुनवाई कर रही है और अपीलीय न्यायालय कानून में किसी भी बाद के परिवर्तन पर विचार करने का हकदार है जो अपील के लंबित रहने के दौरान अस्तित्व में आया है। उक्त निर्णय के बल पर यह जोरदार तर्क दिया गया कि अपीलीय न्यायालय की शक्तियां केवल यह देखने तक सीमित नहीं हैं कि क्या प्रथम न्यायालय का निर्णय मुकदमे के निर्णय की तारीख पर पक्षों के अधिकारों के आधार पर सही था, बल्कि कानून में बाद के परिवर्तन पर विचार करने और उसे प्रभावी बनाने के लिए भी सीमित हैं।

राम कुमार [वी. एन. खरे, जे.]

133

जिसके अंतर्गत सह-भागीदार का पूर्व-समावेशन का अधिकार छीन लिया गया है।

अपील की विचाराधीनता। यह सच है कि लच्मेश्वर प्रसाद शुकुल (ऊपर) में

बिहार धन-ऋणदाता अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में, यह निर्धारित किया गया था कि एक बार डिक्री के खिलाफ अपील करने के बाद, मामला फिर से विचाराधीन हो गया और उसके बाद अपीलीय अदालत ने पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया और इसलिए, अपीलीय अदालत को अपील के लंबित रहने के दौरान होने वाले कानून में किसी भी बदलाव पर विचार करने का अधिकार है और ऐसी स्थिति में -

अपीलीय न्यायालय की शक्ति केवल यह पता लगाने तक सीमित नहीं है कि क्या निर्णय

प्रथम दृष्टांत न्यायालय का निर्णय सही था।

यह भी तर्क दिया गया कि संशोधन अधिनियम पूर्वव्यापी है जो भी हो

वाद के निर्णय की तारीख को वादी के पास जो अधिकार था, वह अपील के लंबित रहने के दौरान समाप्त हो गया और इसलिए, वादी का वाद

असफल होना चाहिए। चूँकि दोनों तर्क अतिव्यापी हैं, हम इस पर विचार करेंगे

लछमीश्वर प्रसाद शुकुल बनाम में निर्णय का प्रभाव। केसर लाल चौधरी (ऊपर) थोड़ी देर बाद। इससे पहले 1995 के संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्थापित धारा 15 के प्रभाव पर विचार करना आवश्यक है -

पक्षों के मूल अधिकार। अब हम इस बात की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे कि क्या संशोधन अधिनियम का उक्त प्रावधान पूर्वव्यापी है जैसा कि विद्वान द्वारा आग्रह किया गया है। अपीलार्थी के लिए वकील।

क़ानूनों की व्याख्या पर मैक्सवेल में, 12 वीं संस्करण। का कथन

इस संबंध में कानून इस प्रकार कहा गया है:

" शायद निर्माण का कोई भी नियम इससे अधिक दृढ़ता से स्थापित नहीं है। - कि किसी कानून को पूर्वव्यापी कार्रवाई नहीं दी जानी चाहिए ताकि -

किसी मौजूदा अधिकार या दायित्व को बाधित करना, मामलों के संबंध में अन्यथा

प्रक्रिया का, जब तक कि उस प्रभाव को किए बिना टाला नहीं जा सकता है

अधिनियम की भाषा पर हिंसा। यदि अधिनियम व्यक्त किया जाता है

ऐसी भाषा में जो किसी भी व्याख्या करने में काफी सक्षम हो, उसे ऐसा करना चाहिए

केवल संभावित के रूप में समझा जाए। ' वास्तव में इस नियम के दो पहलू हैं - इसके लिए, "एक अन्य और अधीनस्थ नियम शामिल है, इस प्रभाव के लिए कि

कानून का अर्थ इस तरह से नहीं लगाया जाना चाहिए कि इसका अधिक पूर्वव्यापी होना चाहिए।

इसकी भाषा की तुलना में संचालन आवश्यक बनाता है।

फ्रांसिस बेनिओन की सांविधिक व्याख्या, द्वितीय संस्करण में, बयान

कानून का उल्लेख इस प्रकार किया गया है:

" कानूनी प्रणाली का आवश्यक विचार यह है कि वर्तमान कानून को शासन करना चाहिए।

वर्तमान गतिविधियाँ। इस कृति में कहीं और एक विशेष अधिनियम की तुलना की गई है।

एक फ्लडलाइट को चालू या बंद करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2001] एसयूपी के लिए कानून का सामान्य निकाय।

1 एस सी आर।

परिवेष्टित वायु। बेढंगा होने के बावजूद ये छवियाँ दिखाती हैं

पूर्वव्यापी कानूनों की अयोग्यता। अगर हम आज कुछ करते हैं,

हम महसूस करते हैं कि उस पर लागू होने वाला कानून आज लागू होना चाहिए,

कल का इसका पिछड़ा हुआ समायोजन नहीं। हमारा मानना है कि

कानून की प्रकृति। पूर्व पोस्ट फैक्टर कानून की नापसंदगी संयुक्त राज्य में निहित है

राज्य के संविधान और कई अमेरिकी राज्यों के संविधान में,

(कानून आगे देखता है, पीछे नहीं)। विल्स के रूप में, जे. ने पूर्वव्यापी कहा विधान इस सामान्य सिद्धांत के विपरीत है कि

जिसे मानव जाति के आचरण को विनियमित किया जाना चाहिए, जब

पहली बार पेश किया गया, भविष्य के कृत्यों से निपटने के लिए, और नहीं होना चाहिए

विश्वास पर किए गए पिछले लेनदेन के चरित्र को बदलने के लिए

तत्कालीन विद्यमान कानून "।

गरिकापति वीराया बनाम। एन. सुब्बैया चौधरी, [1957] एससीआर 488 यह

इस प्रकार देखा गया:

" निर्माण का सुनहरा नियम यह है कि कुछ भी नहीं होने पर

अधिनियम में यह दिखाने के लिए कि इसका पूर्वव्यापी संचालन होना है, यह

इसका इस तरह से अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि कानून में बदलाव का प्रभाव पड़े

मुकदमे में उस समय के दावे पर लागू होता है जब अधिनियम था

.

पास हो गया "।

श्रीमती में। दयावैत और अन्र। वी. इंदरजीत और ओआरएस। , [1966] 3 एस. सी. आर. 275, यह l इस प्रकार है:

" अब एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में, यह स्वीकार किया जा सकता है कि आम तौर पर एक अपील न्यायालय एक नए कानून को ध्यान में नहीं रख सकता है, जिसे अपील किए गए निर्णय के दिए जाने के बाद अस्तित्व में लाया गया है, क्योंकि अपील में वादियों के अधिकार मुकदमे की तारीख में लागू कानून के तहत निर्धारित किए जाते हैं। कोक के दिनों से पहले भी, जिसका सिद्धांत-एक नया कानून संभावित होना चाहिए, न कि इसके संचालन में पूर्वव्यापी होना चाहिए-उद्धृत किया गया है, अदालतों ने उन कानूनों पर असहमति के साथ विचार किया है जो निहित अधिकारों को छीन लेते हैं या लंबित मामलों को प्रभावित करते हैं। हालाँकि, प्रक्रिया के मामले अलग हैं और प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कानून हमेशा पूर्वव्यापी होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक निरपेक्ष है

मूल अधिकारों की अनुल्लंघनीयता का नियम। यदि नया कानून ऐसी भाषा में बोलता है, जो स्पष्ट रूप से या स्पष्ट इरादे से समान रूप से लागू होती है।

लंबित मामलों में, विचारण न्यायालय के साथ-साथ अपील न्यायालय को इस प्रकार व्यक्त किए गए इरादे को ध्यान में रखना चाहिए, और अपील न्यायालय प्रथम श्याम सुंदर वी. राम कुमार (वी. एन. खरे, जे.) की अदालत के फैसले के बाद भी ऐसी कानून को प्रभावी बना सकता है।

उदाहरण "।

हितेन्द्र विष्णु ठाकुर और ओआरएस में। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य। 4] 4 एस. सी. सी. 602 इस न्यायालय ने संशोधन की सीमा और दायरा निर्धारित किया।

और इसका पूर्वव्यापी संचालन इस प्रकार है:

" (¡) एक क़ानून जो मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, उसे संचालन में संभावित माना जाता है जब तक कि स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से पूर्वव्यापी नहीं किया जाता है, जबकि एक क़ानून जो केवल प्रभावित करता है।

प्रक्रिया, जब तक कि इस तरह की रचना पाठ्य रूप से असंभव नहीं है, इसके अनुप्रयोग में पूर्वव्यापी माना जाता है, इसे एक विस्तारित अर्थ नहीं दिया जाना चाहिए और इसे सख्ती से इसके स्पष्ट रूप से सीमित किया जाना चाहिए।

निर्धारित सीमाएँ।

((ii) मंच और सीमा से संबंधित कानून प्रक्रियात्मक प्रकृति का है, जबकि कार्रवाई के अधिकार और अपील के अधिकार से संबंधित कानून भले ही उपचारात्मक प्रकृति का हो। ((iii) प्रत्येक वादी को मूल कानून में निहित अधिकार है लेकिन ऐसा कोई अधिकार नहीं है।

अधिकार प्रक्रियात्मक कानून में मौजूद है।

((iv) एक प्रक्रियात्मक क़ानून को आम तौर पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए, जहां परिणाम नई अक्षमताओं या दायित्वों को पैदा करना या पहले से ही लेनदेन के संबंध में नए कर्तव्यों को लागू करना होगा। पूरा किया।

(v) एक कानून जो न केवल प्रक्रिया को बदलता है, बल्कि नए अधिकारों और देनदारियों का भी निर्माण करता है, को संभावित माना जाएगा। संचालन जब तक कि अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा।

के. एस. परिपूर्णन बनाम। केरल राज्य और अन्य। , [1994] 5 एस. सी. सी. 593 @6, यह न्यायालय लंबित कार्यवाहियों में भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन के प्रभाव पर विचार करते हुए इस प्रकार अभिनिर्धारित करता है:

..... तत्काल मामले में हम संशोधन अधिनियम द्वारा शुरू की गई धारा 23 की उप-धारा 1 (1-ए) के प्रावधानों को उन अधिग्रहण कार्यवाहियों पर लागू करने से संबंधित हैं जो संशोधन अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को लंबित थीं। लंबित कार्यवाहियों के संबंध में, इंग्लैंड में न्यायालयों का दृष्टिकोण यह

है कि वे कानून में परिवर्तनकर्ताओं से अप्रभावित हैं जहां तक वे मूल अधिकारों के निर्धारण से संबंधित हैं और स्पष्ट 136 के अभाव में।

एक संशोधनकारी अधिनियम में एक विपरीत इरादे का संकेत,

द्वारा निर्धारित की जाने वाली कार्रवाई के लिए पक्षों के मूल अधिकार

कानून जैसा कि कार्रवाई शुरू होने के समय मौजूद था और यह इस प्रकार है

क्या पहले मामले की सुनवाई से पहले कानून में बदलाव किया गया है

उदाहरण या अपील लंबित होने के दौरान (हैल्सबरी के कानून देखें) इंग्लैंड, चौथा संस्करण।, खण्ड. 44 , पैरा 922) "।

उपरोक्त निर्णयों से जो कानूनी स्थिति सामने आती है वह यह है कि

जब किसी अधिनियम के निरसन के बाद कोई नया विधान बनाया जाता है तो ऐसा विधान बनाया जाता है।

मुकदमे की तारीख पर पक्षों के मूल अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है या

मुक़दमे का न्यायनिर्णयन जब तक कि ऐसा कोई विधान पूर्वव्यापी न हो और

अपील के बाद अस्तित्व में लाए गए नए कानून को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

जिस निर्णय से अपील की गई है, वह इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके अधिकार

अपील में पक्षकारों का निर्धारण मुकदमे की तारीख को लागू कानून के तहत किया जाता है। हालांकि, संबंधित मामलों में कानून की स्थिति अलग होगी।

प्रक्रियात्मक कानून के लिए लेकिन जहां तक पक्षों के मूल अधिकारों का संबंध है वे अधिनियम में संशोधन से अप्रभावित रहते हैं। इसलिए हम हैं,

इस दृष्टिकोण से कि जहां किसी अधिनियम के प्रावधानों के निरसन का पालन किया जाता है

एक संशोधन अधिनियम द्वारा नया कानून इस तरह का कानून लागू होने की संभावना है।

और पार्टियों के मूल या निहित अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है जब तक कि

अपनी भाषा की तुलना में संचालन आवश्यक बनाता है, लेकिन एक संशोधन अधिनियम जो प्रक्रिया को पूर्वव्यापी माना जाता है, जब तक कि अधिनियम में संशोधन नहीं किया जाता है

अन्यथा प्रदान करता है। हमने संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा मूल अधिनियम में लाई गई नई प्रतिस्थापित धारा 15 पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया है, लेकिन यह भी नहीं पाया है स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा संचालन में पूर्वव्यापी जो हो सकता है

मुकदमे के निर्णय की तारीख पर पक्षों के अधिकार को प्रभावित करता है और इसे अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार में लिया जाना आवश्यक है। शांतिदेवी (श्रीमती) और अन्र में। वी. हुकुम चंद, [1996] 5 एस. सी. सी. 768 इस न्यायालय को प्रतिस्थापित धारा 15 की व्याख्या करने का अवसर मिला था, जिससे हम संबंधित हैं और यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 15 के एक सादे पठन पर यह स्पष्ट है कि इसे संभावित रूप से पेश किया गया है और ऐसी धारा का किसी भी तरह से प्रभावित करने का कोई सवाल ही नहीं है जो उच्च न्यायालय द्वारा दूसरी अपील में पुष्टि किए गए पूर्व-प्रवर्तन के लिए मुकदमे में पारित निर्णय और डिक्री को प्रभावित करती है। हम उक्त निर्णय में व्यक्त विचार से सम्मानपूर्वक सहमत हैं और मानते हैं कि प्रतिस्थापित धारा 15

यह दिखाने के लिए कि यह पूर्वव्यापी है, इसमें कुछ भी न होने पर, उन पक्षों के अधिकार को प्रभावित नहीं करता है जो मुकदमे की तारीख को या पहली बार के न्यायालय द्वारा डिक्री पारित करने की तारीख को उन्हें अर्जित हुए थे।

हम भी श्याम सुंदर वी के हैं। राम कुमार [वी. एन. खरे, जे.]

137

यह विचार कि वर्तमान अपीलें अब तक कानून में परिवर्तन से अप्रभावित हैं पक्षकारों के मूल अधिकारों के निर्धारण से संबंधित और समान

पूर्व-प्रवर्तन के कानून के आलोक में निर्णय लेने की आवश्यकता है क्योंकि यह अस्तित्व में है

डिक्री के पारित होने की तारीख।

लछमीश्वर प्रसाद शुकुल बनाम में निर्णय पर आते हैं। केसर लाल

अपीलार्थी, उक्त मामले के तथ्यों और प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक है। कानून की जिसकी व्याख्या संघीय न्यायालय द्वारा की गई थी। उक्त मामले में,

वादी बंधक संपत्ति की बिक्री द्वारा धन की वसूली के लिए एक मुकदमा लाया।

मुकदमा आंशिक रूप से तय किया गया था। के लिए एक अपील और क्रॉस-अपील थी उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के समक्ष उठाई गई दलीलों में से एक यह थी कि

बिहार धन-ऋणदाता अधिनियम (1938 का 3) की धारा 11 जिसके द्वारा अधिनियमित किया गया था

उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान बिहार विधानमंडल

शून्य है। दलीलों को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 11 का फैसला सुनाया

शून्य होना। इसके बाद, प्रतिवादियों ने संघीय अदालत के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी।

अधिनियम 1939। अधिनियम की धारा 7 (1939 का अधिनियम संख्या 7) जिसके लिए आई थी - संघीय न्यायालय के समक्ष विचार निम्नानुसार है:

" किसी अन्य कानून में निहित इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद

या कानून के बल वाली किसी भी चीज़ में या किसी समझौते में, कोई अदालत नहीं किसी साहूकार द्वारा इससे पहले या बाद में लाए गए किसी भी मुकदमे में

इस अधिनियम का प्रारंभ या किसी अपील या पुनरीक्षण की कार्यवाही में ऐसे वाद से उत्पन्न होने वाले, ब्याज की राशि के लिए एक डिक्री पारित करें

वाद की स्थापना से पूर्व की अवधि, जिसके साथ-साथ न्यायालय के माध्यम से या अन्यथा ब्याज के रूप में पहले से जारी की गई कोई राशि,

अग्रिम ऋण की राशि से अधिक है, यदि ऋण आधारित है

एक दस्तावेज, जिसमें उल्लिखित ऋण की राशि, या इसके द्वारा प्रमाणित दस्तावेज़ "।

(जोर दिया गया)

1939 के अधिनियम 7 के पारित होने के बाद, संघीय के समक्ष यह तर्क दिया गया था

अदालत ने कहा कि प्रतिवादी अधिनियम की धारा 7 के लाभ के हकदार हैं

1939 जबकि उत्तरदाताओं का तर्क इस सिद्धांत पर आधारित था कि सुनवाई

एक अपील अपीलीय न्यायालय केवल यह देखने के लिए चिंतित था कि क्या न्यायालय का निर्णय उस समय के कानून के अनुरूप था या नहीं, वह निर्णय दिया गया था और आगे यह कि 1939 का अधिनियम उस समय अधिनियमित नहीं किया गया था जब उच्च न्यायालय ने मामले का फैसला किया था, संघीय न्यायालय 138

एस सी आर।

नया अधिनियम। उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में, संघीय न्यायालय ने जबकि अधिनियम की धारा 7 की व्याख्या करने का विचार था कि धारा 7 के संदर्भ में

अधिनियम और यह कि अपील में डिक्री अभी तक पारित नहीं की जानी है। द. संघीय न्यायालय ने यह पाए जाने के बाद कि धारा 7 पूर्वव्यापी है, यह अभिनिर्धारित किया कि

अपीलीय न्यायालय को विधायी परिवर्तनों पर विचार करने और उन्हें प्रभावी बनाने की आवश्यकता है

सूट की निरंतरता। इसी संदर्भ में, लछमीश्वर प्रसाद में निर्णय लिया गया है। शुकुल वी. केशवरलाल चौधरी को समझना होगा। जहाँ का निरसन

संचालन, एक अपीलीय न्यायालय को परिवर्तन को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है कानून में लेकिन अपील का निपटारा करने के लिए पूर्व-नियुक्ति के अधिकार के आधार पर

वाद के निर्णय की तिथि। मामले के उस दृष्टिकोण में निर्णय में

लछमीश्वर प्रसाद बनाम। वर्तमान में केसर लाल (उपरोक्त) का कोई आवेदन नहीं है।

लाल चौधरी का अनुसरण राम लाल बनाम में किया गया। राजा राम, (ऊपर) पंजाब द्वारा और हरियाणा उच्च न्यायालय। उक्त मामले में वादी पूर्व के लिए एक मुकदमा लाया

वाइसिनेज की जमीन पर उत्सर्जन। निचली अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया इस आधार पर कि पानीपत शहर की सीमा के बाहर और उस इलाके में जमीन खराब है

पूर्व-उद्दीपन की कोई प्रथा प्रचलित नहीं थी। अपील पर अपीलीय न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को उलट दिया और मुकदमे का फैसला सुनाया। दूसरी अपील विक्रेता द्वारा उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। अपील के लंबित रहने के दौरान, राज्य विधानमंडल ने पंजाब के अधिनियम संख्या 10 में संशोधन करके पंजाब छूट अधिनियम में संशोधन किया।

1960. उक्त संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम की धारा 15 को हटा दिया गया और

इसके स्थान पर नई धारा 15 को प्रतिस्थापित किया गया था जिसके तहत उन आधारों को हटा लिया गया था जिन पर शहरी संपत्ति को पहले से खाली किया गया था। नया प्रतिस्थापित खंड 31 इसके अलावा यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी अदालत संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में स्थापित किए गए वाद में डिक्री पारित नहीं करेगी जो अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत है। उच्च न्यायालय ने आवेदन किया

लच्मेश्वर प्रसाद शुकुल के मामले में निर्धारित सिद्धांतों में कहा गया है कि एक अपील मुकदमे की निरंतरता होने के कारण, अपीलीय न्यायालय को कानून में बाद के परिवर्तन को ध्यान में रखना है जिसका पूर्वव्यापी संचालन है। राम लाल बनाम में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का उक्त निर्णय। राजा राम को राम सरूप बनाम में अनुमोदित किया गया था। मुंशी और ओआरएस। (ऊपर)। उक्त मामले में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि 1960 के संशोधन अधिनियम 10 की धारा 31 संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले अर्जित बिक्री को पूर्वव्यापी करने का अधिकार होने के कारण विफल हो गई। संविधान पीठ ने यह भी नोट किया और समझाया कि लच्मेश्वर प्रसाद शुकुल बनाम। केसर लाल चौधरी (ऊपर), संघीय न्यायालय धारा 7 श्याम सुंदर बनाम का अर्थ लगा रहा था।

राम कुमार [वी. एन. खरे, जे.]

139

बिहार धन-ऋणदाता अधिनियम जिसका पूर्वव्यापी संचालन था और जिसमें संदर्भ में अभिनिर्धारित किया गया कि अपील मुकदमे की निरंतरता होने के कारण, अपीलीय न्यायालय है

कानून में बाद के परिवर्तन को ध्यान में रखना आवश्यक है। यह उचित है कि

राम सरूप के मामले से निम्नलिखित अंश को पुनः प्रस्तुत करें।

" यद्यपि हम सहमत हैं कि पूर्वव्यापी के खिलाफ एक धारणा है

एक क़ानून का संचालन और संबंधित सिद्धांत कि एक क़ानून करेगा

इसकी तुलना में एक बड़ा पूर्वव्यापी संचालन होने के लिए नहीं माना जाता है

भाषा आवश्यक बनाती है, हम मानते हैं कि वर्तमान मामले में

धारा 31 में प्रयुक्त भाषा सरल और व्यापक है ताकि - मूल प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए एक अपीलीय अदालत की आवश्यकता होती है

संशोधन अधिनियम की क्या उसके समक्ष अपील एक के विरुद्ध है पूर्व अनुमति देने वाली या उस राहत से इनकार करने वाली डिक्री। फैसला

लछमीश्वर प्रसाद बनाम में संघीय न्यायालय का। केशवर लाल

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने इस मामले को पूरी तरह से कवर किया।

वहाँ उठाया गया प्रश्न संघीय न्यायालय के कर्तव्य से संबंधित था जब अपील की गई डिक्री के बाद एक संशोधन अधिनियम अधिनियमित किया गया था

पारित होने से पहले प्रतिवादी के अधिकारों में प्रतिकूल हस्तक्षेप किया गया था

अदालत। विद्वान न्यायाधीशों ने माना कि अधिनियम के प्रावधान थे

स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी और उस डिक्री पर लागू किया जाना चाहिए जो था

उसके समक्ष अपील का विषय "।

(जोर दिया गया)

राम स्वरूप बनाम में निर्णय। मुंशी (सुप्रा) के बाद दूसरा आया।

अमीर सिंह और अन्र मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ। वी. राम सिंह और

ओआरएस।, (ऊपर)। आमिर सिंह के मामले में भी इसकी एक और संविधान पीठ है।

पंजाब संशोधन अधिनियम 1960 द्वारा शुरू की गई धारा 31 की व्याख्या करते हुए न्यायालय

यह दोहराया गया कि धारा 31 के पूर्वव्यापी संचालन में अनिवार्य रूप से अपीलीय न्यायालय द्वारा संशोधित धारा 15 के मूल प्रावधानों को प्रभावी बनाया जाना शामिल है, चाहे उसके समक्ष अपील पूर्व-प्रवर्तन देने वाली डिक्री के खिलाफ हो या उस राहत को अस्वीकार करने वाली हो।

यह देखा जा सकता है कि वाक्यांश विज्ञान और शब्द "पहले और बाद में"

बिहार धन-ऋणदाता अधिनियम 1939 की धारा 7 में उपयोग किया गया "कोई भी अदालत इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में लाए गए किसी भी मुकदमे में नहीं आएगी" और पंजाब संशोधन अधिनियम 1960 की धारा 10 की धारा 31 में "कोई भी अदालत पूर्व-प्रवर्तन के लिए एक मुकदमे में डिक्री पारित नहीं करेगी चाहे वह अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में स्थापित की गई हो" इस न्यायालय की संविधान पीठ ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित किया कि अधिनियम में आवश्यक इरादा है, कि इसका पूर्वव्यापी संचालन है और इसे अपीलीय अदालत और अपील की शक्तियों द्वारा विचार में लिया जाना चाहिए।

} 140

एक अपीलीय न्यायालय यह देखने के लिए सीमित नहीं है कि क्या परीक्षण का निर्णय अदालत सही थी या नहीं।

अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील ने दृढ़ता से एक निर्णय पर भरोसा किया

अधिनियम 1973 जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि अधिनियम के प्रारंभ पर और उससे न्यायालय किसी भी मुकदमे में पूर्व-प्रवर्तन के लिए डिक्री पारित करेगा। उक्त न्यायालय में

लछमीश्वर प्रसाद शुकुल बनाम में निर्धारित सिद्धांतों को लागू करते हुए मामला।

केसर लाल चौधरी, (ऊपर) ने अभिनिर्धारित किया कि एक अपील के रूप में पुनः सुनवाई की जा रही है, यह होगा

उच्च न्यायालय को उस अपील को स्वीकार करना था और उच्च न्यायालय के पास यही है किया। अमरजीत कौर में उक्त निर्णय का साधु सिंह में पालन किया गया और

एन. आर. वी. धरम देव और ओआरएस। , ए. आई. आर. (1980) एस. सी. 1654 जिसमें यह न्यायालय

दोहराया कि अधिनियम की धारा 3 डिक्री के पारित होने में भी बाधा डालती है

अपील में क्योंकि अपील मुकदमे की पुनः सुनवाई कर रही है। दोनों मामलों में यह न्यायालय

यह जाँच किए बिना कि क्या अधिनियम की धारा 3 संभावित है या नहीं।

लछमीश्वर में संघीय न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया

प्रसाद शुकुल बनाम। केशवर लाल चौधरी का मामला। हमें आपूर्ति नहीं की गई है

अधिनियम के पूर्ण पाठ के साथ और इसकी अनुपस्थिति में, हम यह निष्कर्ष निकालने में असमर्थ हैं कि उक्त अधिनियम या तो संभावित था या पूर्वव्यापी था। ऐसा प्रतीत होता है,

यह न्यायालय इस धारणा पर आगे बढ़ा कि अधिनियम की धारा 3 पूर्वव्यापी थी और इसलिए, लच्मेश्वर प्रसाद शुकुल बनाम में निर्धारित सिद्धांत को लागू किया। केशवर लाल चौधरी, (ऊपर)। ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ये निर्णय अपीलार्थियों के मामले में कोई सहायता नहीं करते हैं।

तर्क के दौरान, एक अधूरे मन का तर्क उठाया गया कि एक संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किए गए अधिनियम में एक प्रतिस्थापित धारा को माना जाना चाहिए। पूर्वगामी संचालन होना। विद्वान वकील के अनुसार

अपीलार्थी, एक अधिनियम में एक प्रतिस्थापित धारा का कार्य पक्षों के अधिकारों को मिटा देना है जैसे कि वे कभी मौजूद नहीं थे। इस तर्क को केवल अस्वीकार करने के लिए नोट किया गया है। एक अधिनियम में एक प्रतिस्थापित धारा एक संशोधन अधिनियम का उत्पाद है और एक संशोधन अधिनियम के मामले में आने वाले सभी प्रभाव और परिणाम एक अधिनियम में प्रतिस्थापित धारा के मामले में भी होंगे।

अगले प्रश्न पर आते हुए, बाद में अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील

पूर्व-अधिग्रहण के अधिकार को पुरातन और सामंती बताते हुए तर्क दिया कि

प्रतिस्थापित धारा 15 नागरिकों के सामान्य लाभ के लिए अधिनियमित एक लाभकारी विधान होने के कारण, इस न्यायालय को इसका अर्थ लगाते हुए, परोपकारी श्याम सुंदर v के नियम को लागू करने की आवश्यकता है।

राम कुमार [वी. एन. खरे, जे.]

141

धारा 15 को पूर्वव्यापी संचालन दिया जाना चाहिए। आम तौर पर नियम व्याख्या न्याय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में न्यायालय की सहायता करने के लिए होती है।

इसलिए, यह परोपकारी निर्माण के नियम के अनुप्रयोग के मामले में सच है।

भी। यदि परोपकारी निर्माण के नियम के लागू होने पर, न्यायालय यह पाता है कि

ऐसा प्रतीत होता है कि यह कानून के मापदंडों के भीतर न्याय कर रहा होगा वर्तमान मामले में निर्माण का ऐसा नियम क्यों लागू नहीं किया जाए। लेकिन

न्यायालय की शक्तियों की सीमाएँ हैं, इस अर्थ में कि कुछ स्थितियों में न्यायालय अक्सर स्वयं को परोपकारी या अन्य नियमों को लागू करने से रोकते हैं।

उदार निर्माण। न्यायिक पूर्ववर्ती ने निर्धारित किया है कि, आम तौर पर,

परोपकारी निर्माण के नियम को कहाँ और कब लागू करने की आवश्यकता है

और लागू नहीं किया जाना चाहिए। स्थितियों में से एक यह है कि जब न्यायालय को पता चलता है कि

परोपकारी निर्माण के नियम को लागू करना यह होगा कि एक

प्रयुक्त शब्दों को प्रतिस्थापित करके, जोड़कर या बदलकर क़ानून का प्रावधान

अधिनियम के प्रावधान में। ऐसी स्थिति में आम तौर पर अदालतों ने परहेज किया है।

स्वयं परोपकारी निर्माण के नियम को लागू करने के लिए। परोपकारी निर्माण के नियम के आवेदन के आवरण के तहत एक न्यायालय फिर से अधिकार नहीं रखता है

एक कानून के प्रावधान को कानून बनाना और कानून की भावना के साथ हिंसा करना।

अधिनियम के प्रावधान का इस प्रकार अर्थ लगाया गया है। दूसरी स्थिति यह है कि जब शब्द

कानून में उपयोग केवल एक अर्थ के लिए सक्षम है। ऐसी स्थिति में,

यह पाया गया है कि कानून में उपयोग किए गए शब्द एक से अधिक को जन्म देते हैं अर्थात्, ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय इस तरह के आवेदन करने से वंचित नहीं हैं।

निर्माण का नियम। तीसरी स्थिति तब होती है जब इस तरह से माने गए क़ानून के प्रावधान में कोई अस्पष्टता नहीं होती है। यदि किसी कानून का प्रावधान स्पष्ट, असंदिग्ध है और किसी भी संदेह को जन्म

नहीं देता है, तो ऐसी परिस्थितियों में परोपकारी निर्माण का नियम लागू नहीं होता है। लेकिन अगर यह पाया जाता है

कि किसी अधिनियम के प्रावधानों में उपयोग किए गए प्रावधान या शब्द के अर्थ के संबंध में संदेह है, न्यायालय के लिए अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए परोपकारी निर्माण के नियम को लागू करने की अनुमति है। आम तौर पर, कल्याण का अर्थ लगाते हुए परोपकारी निर्माण का नियम लागू किया गया है।

कमजोर और मजबूत के बीच संबंधों से संबंधित कानून या प्रावधान

अनुबंध करने वाले पक्ष। यह मानते हुए कि संशोधन अधिनियम लोगों की सामान्य भलाई के लिए है, हम ऐसी वनहीन स्थितियों की उपस्थिति नहीं पाते हैं जो प्रतिस्थापित धारा 15 का अर्थ लगाते हुए इस तरह के नियम को लागू करने की आवश्यकता हो सकती है।

संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रतिस्थापित धारा 15 के पढ़ने से पता चलेगा कि उसमें उपयोग किए गए शब्द सरल और सरल हैं और इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। अनुभाग में उपयोग किए गए शब्द एक से अधिक नहीं होते हैं।

अर्थ। इसके अलावा, हम यह नहीं पाते हैं कि अधिनियम में संशोधन या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से पूर्वव्यापी है। यदि हम मानते हैं कि संशोधन अधिनियम 142 है।

एस सी आर।

संचालन में पूर्वव्यापी, हम जोड़कर अधिनियम को फिर से कानून बना रहे होंगे

शब्द जो संशोधन अधिनियम में या तो स्पष्ट रूप से या द्वारा नहीं पाए जाते हैं

आवश्यक इरादा और यह भावना के साथ हिंसा करने के बराबर होगा

संशोधन अधिनियम। इन कारणों से, परोपकारी शासन का अनुप्रयोग

प्रतिस्थापित धारा 15 का अर्थ लगाते समय निर्माण पूरी तरह से लागू नहीं होता है।

विद्वान वकील ने तब तर्क दिया कि चूंकि संशोधन अधिनियम एक है

लाभकारी कानून, इसमें पूर्वव्यापीता निहित है। मान लीजिए, इसके लिए इस तर्क का कि मुक्ति का अधिकार एक सामंती या पुरातन कानून है और

इसलिए, संशोधन अधिनियम सामान्य लोगों के लिए एक लाभकारी कानून है।

नागरिकों को लाभ लेकिन निर्माण का ऐसा कोई नियम नहीं है जो इस तरह के कानून के बावजूद कानून हमेशा पूर्वव्यापी होता है।

या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से पूर्वव्यापी नहीं बनाया जाता है। में मोती राम बनाम का मामला सूरज भान और ओआरएस। , [1960] 2 एस. सी. आर. 896 का आयोजन इस प्रकार किया गया था:

" यह स्पष्ट है कि किया गया संशोधन किसी भी प्रक्रिया के संबंध में नहीं है और इसे प्रक्रियात्मक नहीं माना जा सकता है। यह एक मामले में है यह मूल कानून है क्योंकि यह मकान मालिक के मूल अधिकार को प्रभावित करता है।

यह स्वीकार किया जा सकता है कि अधिनियम का उद्देश्य राहत प्रदान करना है

किरायेदार और उस अर्थ में एक लाभकारी उपाय है और इस तरह इसके

प्रावधान का उदारतापूर्वक निर्माण किया जाएगा; लेकिन यह सिद्धांत नहीं होगा

यह प्रश्न तय करने में सामग्री या प्रासंगिक भी हो कि क्या

नया प्रावधान पूर्वव्यापी है या नहीं। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जहाँ

एक संशोधन निहित अधिकारों को प्रभावित करता है जो संशोधन कार्य करेगा

संशोधन अधिनियम स्पष्ट रूप से प्रासंगिक प्रावधान नहीं करता है संदर्भ में पूर्वव्यापी और हम सुझाव को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं देखते हैं

कि प्रासंगिक प्रावधान के पूर्वव्यापी संचालन की वर्तनी की जा सकती है

आवश्यक निहितार्थ के रूप में "।

हम मोती राम बनाम में लिए गए दृष्टिकोण के साथ सम्मानजनक सहमति में हैं।

सूरज भान और ओआरएस।, (ऊपर)। पूर्व-अधिकार का अधिकार एक कमजोर अधिकार हो सकता है लेकिन फिर भी अधिकार को कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसकी अनुमति दी जा सकती है

कानून के मापदंडों के भीतर पराजित। एक कानून जो मूल अधिकार को प्रभावित करता है, उसे तब तक संभावित माना जाना चाहिए जब तक कि स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से पूर्वव्यापी नहीं किया जाता है। अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने रफीक्वेनेसा बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर दृढ़ता से भरोसा किया। लाल बहादुर छेत्री (मृत) अपने प्रतिनिधियों और अन्य लोगों के माध्यम से।, [1964] 6 एस. सी. आर. 876 @883 इस तर्क के लिए कि विधान द्वारा अधिनियमित एक लाभकारी प्रावधान को पूर्वव्यापी संचालन दिया जाना चाहिए। उक्त मामले में यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया:

श्याम सुंदर बनाम। राम कुमार [वी. एन. खरे, जे.]

143

" यह प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि विधायिका चाहती थी

अधिनियम के प्रवर्तन से पहले निष्पादित किया गया। दूसरे शब्दों में, पट्टे जिन्हें अधिनियम लागू होने से पहले बनाया गया था, उन्हें प्राप्त करने का इरादा है

अधिनियम के प्रावधानों का लाभ, और उस अर्थ में, अधिनियम

स्पष्ट रूप से उन मकान मालिकों के निहित अधिकारों को प्रभावित करता है जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया था अधिनियम की तारीख से पहले किरायेदारों को शहरी संपत्तियाँ। वह एक है।

महत्वपूर्ण तथ्य जो दायरे और प्रभाव को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है

एस. 5 . "

उक्त मामले में अधिनियम की धारा 2 में प्रावधान किया गया है कि किसी अनुबंध या तत्काल लागू किसी कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, उक्त अधिनियम के प्रावधान उन सभी गैर-कृषि किरायेदारों पर लागू होंगे, चाहे वे इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से पहले या बाद में बनाए गए हों। धारा 5 उन किरायेदारों को सुरक्षा प्रदान करती है जिन्होंने आवासीय या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उन्हें पट्टे पर दी गई भूमि पर अपने पक्ष में निष्पादित पट्टों की तारीख से 5 साल के भीतर निर्माण किया है। अधिनियम की धारा 2 और 5 का अर्थ लगाते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 2 और धारा 5 अपने प्रावधानों को पूर्वव्यापी बनाने के विधायी इरादे का एक स्पष्ट संकेत देते हैं। उक्त कारणों से निर्णय का कोई अनुप्रयोग नहीं है।

वर्तमान मामले में।

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तब इस निर्णय पर भरोसा किया

एच. शिव राव और अन्र के मामले में न्यायालय। वी. सेलेलिया परेरा और ओआरएस। , [1987] 1 एस. सी. सी. 258 इस प्रस्ताव के लिए कि एक लाभकारी कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाना चाहिए। उक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि अभिव्यक्तियाँ अस्पष्ट हैं, तो कानून के उद्देश्य को पूरा करने वाले निर्माण को अर्थ की कुंजी प्रदान करनी चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हम पहले ही मान चुके हैं कि प्रतिस्थापित धारा 15 में कोई अस्पष्टता नहीं है और इसलिए, इस निर्णय का वर्तमान मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है। तदनुसार हम अपीलार्थियों के विद्वान वकील की दलीलों को अस्वीकार करते हैं।

अंत में, अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि

अधिनियम जिसके द्वारा अधिनियम की नई धारा 15 को प्रतिस्थापित किया गया है, घोषणात्मक है और इसलिए इसका पूर्वव्यापी संचालन है। आम तौर पर जब कोई अधिनियम पिछले कानून की घोषणा करता है, तो उसे पूर्वव्यापी प्रभाव देने की आवश्यकता होती है। एक घोषणात्मक क़ानून का कार्य एक चूक प्रदान करना या पिछले क़ानून की व्याख्या करना है और जब ऐसा कोई अधिनियम पारित किया जाता है, तो यह तब प्रभावी होता है जब पिछला अधिनियम पारित किया गया था। कानून बनाने की विधायी शक्ति में सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2001] का समर्थन शामिल है।

144

यह घोषित करना कि पूर्ववर्ती विधि क्या थी और ऐसा घोषणात्मक अधिनियम कब है

हमेशा पारित होने पर इसे पूर्वव्यापी माना गया है। केवल उपयोग का अभाव

किसी अधिनियम में 'घोषणा' शब्द की व्याख्या करते हुए कि पहले कानून क्या था एक घोषणात्मक अधिनियम प्रतीत होता है लेकिन यदि न्यायालय किसी अधिनियम को घोषणात्मक पाता है

या व्याख्यात्मक इसे पूर्वव्यापी के रूप में समझा जाना चाहिए। इसके विपरीत जहाँ ए

कानून 'घोषणात्मक' शब्द का उपयोग करता है, इस प्रकार उपयोग किए गए शब्द पर्याप्त नहीं हो सकते हैं

यह अभिनिर्धारित करना कि कानून एक घोषणात्मक अधिनियम है क्योंकि शब्दों का उपयोग क्रम में किया जा सकता है

नया कानून लागू करना।

कानून पर क्रेज़, 7 वें संस्करण में कानून के कथन को इस प्रकार कहा गया है:

" यदि कोई संदेह महसूस किया जाता है कि किसी विशेष पर सामान्य कानून क्या है

विषय, और सामान्य कानून की व्याख्या और घोषणा करने के लिए एक अधिनियम पारित किया जाता है,

ऐसे अधिनियम को घोषणात्मक अधिनियम कहा जाता है।

वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों पर जी. पी. सिंह ने क्रेज़ के हवाले से कहा

इस प्रकार:

" आधुनिक उद्देश्यों के लिए एक घोषणात्मक अधिनियम को एक अधिनियम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है -

सामान्य कानून के बारे में मौजूद संदेह को दूर करें, या अर्थ या

किसी भी कानून का प्रभाव। इस तरह के अधिनियमों को आमतौर पर पूर्वव्यापी माना जाता है।

एक घोषणात्मक अधिनियम पारित करने का सामान्य कारण यह है कि क्या अलग रखा जाए

संसद एक न्यायिक त्रुटि मानती है, चाहे सामान्य कानून का विवरण या कानूनों की व्याख्या में।

आमतौर पर, यदि निश्चित रूप से नहीं, तो ऐसे अधिनियम में एक प्रस्तावना होती है और

'घोषित' शब्द के साथ-साथ 'अधिनियमित' शब्द भी। लेकिन "यह घोषित किया गया है" शब्दों का उपयोग निर्णायक नहीं है कि अधिनियम के लिए घोषणात्मक है।

इन शब्दों का उपयोग कभी-कभी कानून के नए नियमों को लागू करने के लिए किया जा सकता है।

और बाद के मामले में अधिनियम केवल कानून में संशोधन करेगा और

जरूरी नहीं कि यह पूर्वव्यापी हो। इसलिए, प्रकृति को निर्धारित करने में

अधिनियम के अनुसार, पदार्थ को ध्यान में रखा जाना चाहिए न कि

रूप में।

यदि कोई नया अधिनियम किसी पूर्ववर्ती अधिनियम की 'व्याख्या' करने के लिए है, तो यह होगा -

बिना वस्तु के जब तक कि इसका पूर्वव्यापी अर्थ न लगाया जाए। एक व्याख्यात्मक अधिनियम है

आम तौर पर एक स्पष्ट चूक प्रदान करने या संदेह को दूर करने के लिए पारित किया जाता है

पूर्ववर्ती अधिनियम के अर्थ के बारे में। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि कानून उपचारात्मक है या केवल पिछले कानून का घोषणात्मक है।

आम तौर पर पूर्वव्यापी संचालन का इरादा होता है।

केशवलाल जेठालाल शाह बनाम। मोहनलाल भगवानदास और अन्र।

, [1968] श्याम सुंदर बनाम। राम कुमार [वी. एन. खरे, जे.]

145

3 एस. सी. आर. 623, यह न्यायालय संशोधन अधिनियम की धारा 29 (2) की व्याख्या करते हुए, इस प्रकार आयोजित किया गया:

" एक व्याख्यात्मक अधिनियम आम तौर पर एक स्पष्ट चूक प्रदान करने के लिए पारित किया जाता है।

या पिछले अधिनियम के अर्थ के बारे में संदेह को दूर करना। अनुभाग

29 (2) इसके अधिनियमित होने से पहले इसके निहितार्थ में भी सटीक था

जैसा कि इसकी अभिव्यक्ति में; उपयोग किए गए शब्दों का अर्थ संदेह में नहीं था, और इसके वाक्यांश में कोई चूक नहीं थी जिसकी आवश्यकता थी

संशोधन द्वारा प्रदान किया जाएगा।

आर. राजगोपाल रेड्डी (मृत) में एल. आर. एस. और ओआरएस। वी. पद्मिनी

एलआरएस द्वारा चंद्रशेखरन (मृत)। , [1995] 2 एस. सी. सी. 630 का आयोजन इस प्रकार किया गया था:

ऑपरेशन का उद्देश्य आम तौर पर होता है। इसका एक स्पष्टीकरणात्मक संशोधन प्रकृति का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा और इसलिए, यदि प्रमुख

जब संविधान लागू हुआ तो अधिनियम मौजूद कानून था

संशोधन अधिनियम भी मौजूदा कानून का हिस्सा होगा। यदि कोई नया अधिनियम

पूर्ववर्ती अधिनियम की व्याख्या करने के लिए, यह बिना किसी उद्देश्य के होगा जब तक कि इसका अर्थ न लगाया जाए

पूर्वव्यापी। एक व्याख्यात्मक अधिनियम आम तौर पर एक प्रदान करने के लिए पारित किया जाता है

स्पष्ट चूक या के अर्थ के रूप में संदेह को दूर करने के लिए

पिछला अधिनियम "

उपरोक्त निर्णयों से जो कानूनी सिद्धांत उभरता है वह यह है कि

एक घोषणात्मक या व्याख्यात्मक अधिनियम का कार्य एक स्पष्ट चूक प्रदान करना या पिछले अधिनियम के अर्थ के बारे में संदेह को दूर करना है और ऐसा अधिनियम पिछले अधिनियम के पारित होने की तारीख से प्रभावी होता है। अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने दो न्यायाधीशों---------- ---------- वी. प्रेम बिहारी खरे

[1989] 2 एस. सी. सी. 95 उनके तर्क के समर्थन में। उक्त निर्णय में, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988

घोषणात्मक अधिनियम, अधिनियम की धारा 4 के प्रावधान पूर्वव्यापी संचालन करते हैं। अपीलार्थियों के वकील द्वारा इस निर्णय की निर्भरता पूरी तरह से गलत है।

क्योंकि इस निर्णय को आर. राजा गोपाल रेड्डी बनाम में खारिज कर दिया गया था। पद्मिनी चंद्रशेखरन (ऊपर) जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सामान्य कानून या किसी कानून के प्रभाव के अर्थ के बारे में किसी भी संदेह को दूर करने के लिए अधिनियम पारित नहीं किया गया था और इसलिए यह एक घोषणात्मक अधिनियम नहीं था।

हम पहले ही संशोधन अधिनियम की प्रतिस्थापित धारा 15 का हवाला दे चुके हैं लेकिन

यह नहीं पाते हैं कि संशोधन अधिनियम या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा

एक चूक प्रदान करने या के अर्थ के रूप में एक संदेह को दूर करने का इरादा

मूल अधिनियम की पिछली धारा 15। मूल अधिनियम की पिछली धारा 15 सटीक, स्पष्ट और सरल थी, इसमें कोई अस्पष्टता नहीं थी। इसका अर्थ

मूल अधिनियम की धारा 15 में उपयोग किए गए शब्दों में से कभी भी संदेह में नहीं था और इसके वाक्यांश में कोई चूक नहीं थी जिसे प्रदान करने की आवश्यकता थी।

संशोधन अधिनियम द्वारा। इसके अलावा, संशोधन अधिनियम या तो स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से पूर्वव्यापी होने का इरादा नहीं था और इस कारण से हम मानते हैं कि 1995 का संशोधन अधिनियम 10 एक घोषणात्मक अधिनियम नहीं है और इसलिए, इसका कोई पूर्वव्यापी संचालन नहीं है।

वनाच्छादित कारणों से, हम दीदार में लिए गए कानून के दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं

सिंह आदि वी। एलआरएस द्वारा इशर सिंह (मृत)। आदि (ऊपर) और आगे मानते हैं कि रामजीलाल बनाम के मामले में निर्णय। घिसा राम (ऊपर) कानून के बारे में सही दृष्टिकोण नहीं रखता है।

उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि संशोधन अधिनियम

व्यवहार में आने वाला संभावित व्यक्ति पूर्व-प्रवर्तन वाद के निर्णय की तारीख को मुकदमे के पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है और अपीलीय न्यायालय को प्रतिस्थापित धारा 15 को ध्यान में रखने या प्रभावी बनाने की आवश्यकता नहीं है।

संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया।

ऊपर जो कहा गया है, उसे देखते हुए ये अपीलें विफल हो जाती हैं और तदनुसार

खारिज कर दिए जाते हैं, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

याचिका

एं खारिज कर दी गईं।

बी. एस